सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 82, नई दिल्ली । सोमवार, 03 जून 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यदि आप बहाने बनाते हैं मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते।

03 2 जून को जेल,केजरीवाल फेल,कांग्रेस ने किया खेल

06 प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर हंगामा क्यों?

08 दिल्ली, यूपी-बिहार समेत भारत के अधिकांश हिस्सों में लू का कहर

सराय काले खां से शताब्दी नगर तक आरआरटीएस कॉरिडोर तैयार, जानिए दिल्ली में कब चलेगी नमो भारत

करीब 82 किमी लंबा दिल्ली- गाजियाबाद- मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर अब लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली में सभी आरआरटीएस स्टेशनों का निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है और सभी स्टेशन आकार ले चुके हैं। दिल्ली में आरआरटीएस कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 14 किमी है। इसमें से नौ किमी का हिस्सा एलिवेटेड है।

संजय बाटला

नई दिल्ली। करीब 82 किमी लंबा दिल्ली-गाजियाबाद- मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर अब लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली में सभी आरआरटीएस स्टेशनों का निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है और सभी स्टेशन आकार ले चुके हैं।

दिल्ली में आरआरटीएस कॉरिडोर (RRTS Corridor) की कुल लंबाई करीब 14 किमी है। इसमें से नौ किमी का हिस्सा एलिवेटेड है और पांच किमी का हिस्सा भूमिगत है। ये दोनों सेक्शन अब लगभग तैयार हो चुके हैं। दिल्ली में वायाडक्ट निर्माण कार्य पूर्ण होने से सराय काले खां से लेकर मेरठ के शताब्दी नगर तक लगभग 57 किमी के एलिवेटेड हिस्से में वायाडक्ट निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है।

दिल्ली में कितने स्टेशन, और कितना काम हुआ

दिल्ली सेक्शन में सराय काले खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार (भूमिगत) तीन आरआरटीएस स्टेशन हैं, जहां फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही न्यू अशोक नगर स्टेशन से साहिबाबाद के बीच इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एवं सिग्नलिंग कार्यों के साथ-साथ ट्रैक बिछाने की गतिविधियां जारी हैं।

दिल्ली सेक्शन का निर्माण इस साल के अंत तक पूर्ण होने की उम्मीद है, जिसके बाद दिल्ली सेक्शन में भी नमो भारत ट्रेनों का ट्रायल रन शुरू किए जाएंगे और फिर एनसीआरटीसी ट्रेनों का संचालन आरंभ करने की दिशा में अग्रसर होगी।

दिल्ली में आई कई चुनौतियां

अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली सेक्शन में वायाडक्ट के निर्माण के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के समक्ष कई तकनीकी चुनौतियां आई, जिनका सफलतापूर्वक निदान किया गया है। इन चुनौतियों में दिल्ली के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में निर्माण गतिविधियों को क्रियान्वित करना, लंबे स्पेशल स्टील स्पैन का उपयोग करके बारापुला फ्लाईओवर को पार करना, यमुना नदी ब्रिज का निर्माण करना और गाज़ीपुर नाले को पार करने के लिए कोंडली चौक पर छह स्टील स्पेशल स्पैन स्थापित करना शामिल है।

सराय काले खां स्टेशन को वीर हकीकत राय आईएसबीटी, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन जैसे समीप के परिवहन साधनों के साथ सहज एकीकरण के लिए डिजाइन किया गया है।

अक्टूबर से शुरू हो जाएगा ट्रायल

एनसीआरटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसी साल अक्टूबर माह तक नमो भारत का सराय काले खां तक ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। इसके जनवरी या फरवरी 2025 तक यह ट्रेक दिल्ली से मेरठ तक दौड़ने लगेगी। हालांकि दिल्ली में नमो भारत चलाने का लक्ष्य जून 2025 तक रखा गया है। लेकिन फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने के मद्देनजर ट्रेन को उससे पहले ही हरी झंडी दिखाई जा सकती है।

श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर

हादसे में लगभग 25 लोग घायल, सभी का उपचार जारी

बिलासपुर जिले में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी जिसमें करीब नौ महिलाएं और तीन बच्चे सहित करीब 25 लोग घायल हो गए। गाडी में 30 लोग सवार होकर मरही माता दर्शन करने जा रहे थे।

परिवहन विशेष न्यूज

बिलासपुर। जिले में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी जिसमें करीब नौ महिलाएं और तीन बच्चे सहित करीब 25 लोग घायल हो गए। गाडी में 30 लोग सवार होकर मरही माता दर्शन करने जा रहे थे। फिलहाल घायलों को अस्पताल मे भर्ती कराया गया है।

दरअसल रतनपुर थाना क्षेत्र से यह घटना की खबर सामने आई है जहां करीब 30 श्रद्धालुओं से भरी छोटा हाथी में सवार होकर श्रद्धालु मरही माता दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान रतनपुर बेलगहना के बीच ग्राम रानी बछली मोड़ के तरफ से आ रही ट्रक सीजी 15 DY 8312 से टक्कर हो गई।

इस हादसे में करीब गाड़ी मे सवार सभी लोग घायल हो गये जिसे तत्कालिक इलाज के लिए रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाया गया लेकिन घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण 20 लोगों को बिलासपुर के सिम्स रेफर कर दिया गया। सभी घायल बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम कया के रहने वाले हैं। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों में 9 साल की दीपिका, 15 आदित्य और देवेंद्र समेत मोहित, शिवानी, रोहित, सतरूपा, नेहा और अन्य लोग शामिल हैं।

बता दें कि कवर्धा जिले में पिकअप के खाई में गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद प्रदेश में ऐसे माल वाहक वाहनों में यात्री परिवहन पर सख्ती की बात कही गई थी, लेकिन अब भी लोग छोटे माल वाहक वाहनों में बड़ी संख्या में सवार होकर जानलेवा सफर कर रहे हैं।

दिल्ली मेट्रो के फेज चार के दो नए कॉरिडोर को लेकर आया अपडेट, निर्माण की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की एक डाटा के अनुसार फेज चार के इन दोनों कॉरिडोर के निर्माण के लिए इस वर्ष 28 मार्च को 8399 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट स्वीकृत हुआ। इस लागत से इन दोनों कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता हटने के बाद कुछ समय बाद डीएमआरसी इन दोनों कॉरिडोर के निर्माण के लिए टेंडर शुरू कर सकता है।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फेज चार के दो नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया को गति मिलेगी। इसमें इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो कॉरिडोर व लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जिसकी लंबाई 20.76 किलोमीटर होगी। उम्मीद है कि जल्दी ही इन दोनों कॉरिडोर के निर्माण को लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वर्ष के अंत तक साइट पर निर्माण शुरू हो सकता है।

लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 13 मार्च को इन दोनों कॉरिडोर की योजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। इसके अगले ही दिन केंद्र सरकार ने इन दोनों कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया लेकिन अभी तक टेंडर नहीं होने से निर्माण शुरू नहीं हो पाया है।

दोनों कॉरिडोर के निर्माण के लिए टेंडर शुरू

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की एक डाटा के अनुसार फेज चार के इन दोनों कॉरिडोर के निर्माण के लिए इस वर्ष 28 मार्च को 8,399 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट स्वीकृत हुआ। इस लागत से इन दोनों कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता हटने के बाद कुछ समय बाद डीएमआरसी इन दोनों कॉरिडोर के निर्माण के लिए टेंडर शुरू कर सकता है।

लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर का पूरा हिस्सा एलिवेटेड होगा। इसलिए इसके निर्माण की प्रक्रिया पहले शुरू हो सकती है। इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कारिडोर का एक किलोमीटर हिस्सा छोड़कर बाकी हिस्सा भूमिगत होगा। इसलिए इस कॉरिडोर के निर्माण में चुनौतियां ज्यादा होंगी।

मौजूदा समय में एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क

392.44 किलोमीटर है। इसके अलावा फेज चार के तीन कॉरिडोर का निर्माण अभी चल रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फेज चार के निर्माणाधीन तीन प्रमुख कारिडोर को स्वीकृति दी थी। जिसमें जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कारिडोर, मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर व तुगलकाबाद-एरोसिटी कारिडोर शामिल है।

इन तीनों कॉरिडोर की लंबाई 65.20 किलोमीटर होगी। इन तीनों कॉरिडोर का निर्माण पूरा होने पर मेट्रो का नेटवर्क 457.64 किलोमीटर हो जाएगा। फेज चार के दो अन्य कारिडोर का निर्माण पूरा होने पर एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क 478.4 किलोमीटर हो जाएगा।

दोनों मेट्रो कारिडोर की लंबाई, भूमिगत व एलिवेटेड हिस्से की लंबाई (किलोमीटर में)

कॉरिडोर	लंबाई	भूमिगत	एलिवेटेड	एलिवेटेड
लाजपत नगर- साकेत जी	8.385	0.00	8.385	8
इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ	12.377	11.349	1.028	10
कुल	20.762	11.349	9.413	18

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

...हाईवे पर यात्रा महंगी, यहां देखें अब कितना देना होगा टोल टैक्स

भारत में टोल शुल्क मुद्रास्फीति के अनुरूप सालाना संशोधित किए जाते हैं और राजमार्ग संचालकों ने स्थानीय समाचार पत्रों में सोमवार से लगभग 1100 टोल प्लाजा पर 3% से 5% की वृद्धि की घोषणा करते हुए नोटिस दिए हैं। नए दर अब दो जून यानी रविवार रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सोमवार से पूरे देश में सड़क टोल में वृद्धि होने वाला है।

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। नए दर अब दो जून यानी रविवार रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सोमवार से पूरे देश में सड़क टोल शुल्क में 3-5% की वृद्धि होने वाला है। बता दें कि देश में आम चुनावों के कारण अप्रैल में वार्षिक वृद्धि को रोक दिया गया था। भारत में टोल शुल्क मुद्रास्फीति के अनुरूप सालाना संशोधित किए जाते हैं और राजमार्ग संचालकों ने स्थानीय समाचार पत्रों में सोमवार से लगभग 1,100 टोल प्लाजा पर 3% से 5% की वृद्धि की घोषणा करते हुए नोटिस दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो गई है, इसलिए उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) दरों में संशोधन किए गए हैं।

इसे चुनावों के दौरान रोक दिया गया था जो अब 3 जून से प्रभावी हो रहा है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर इतना बढ़ा टोल

मेरठ से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए गाजियाबाद या करनाल हाईवे होते हुए शामली तक जाने वाले वाहन चालकों पर टोल टैक्स की अधिक मार पड़ेगी। रविवार यानी आज रात 12 बजे से मेरठ से सराय काले खां तक जाने वाले कार चालकों को काशी (परतापुर) टोल प्लाजा पर 160 रुपये के बजाय 165 रुपये शुल्क देना होगा। 24 घंटे में दोनों तरफ का शुल्क 230 रुपये के स्थान पर 250 रुपये देना होगा। मेरठ-करनाल हाईवे पर मेरठ से वाया शामली करनाल जाने के लिए वाहन चालकों पर पांच से दस रुपये का बोझ बढ़ेगा। अलग-अलग वाहन श्रेणी के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं।

प्रयागराज से वाराणसी और कौशांबी से प्रतापगढ़ जाने का सफर मंहगा

वहीं, अब प्रयागराज से वाराणसी और कौशांबी से प्रतापगढ़ जाने का सफर मंहगा हो गया है। बताया गया है कि टोल टैक्स में छोटे वाहन जैसे कार व अन्य पर पांच से सात रुपये प्रति किलोमीटर और भारी वाहनों से 25 से 30 रुपये प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। कानपुर-प्रयागराज हाईवे के बीच सर्वाधिक टोल टैक्स बढ़ाया है। इसमें कार से जाने पर फतेहपुर के बड़ौरी टोल प्लाजा में 55 रुपये और कटोघन टोल प्लाजा में 40 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

इन्हें होगा टोल के बढ़ने से फायदा

आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स और अशोक बिल्डकॉन लिमिटेड जैसे उच्च ऑपरेटरों को टोल वृद्धि से लाभ होगा। भारत ने पिछले दशक में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 146,000 किलोमीटर है, जो दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक सड़क नेटवर्क है।

साल दर साल इतना बढ़ा टोल

2018/19 में 252 बिलियन से 2022/23 वित्तीय वर्ष में टोल संग्रह बढ़कर 540 बिलियन रुपये ($6.5 बिलियन) से अधिक हो गया। इसमें सड़क यातायात में वृद्धि के साथ-साथ टोल प्लाजा और शुल्कों की संख्या में वृद्धि से मदद मिली।

पर्यावरण पाठशाला : पानी बचाने और अपने पानी की टंकी की देखभाल करने की अपील

आज के दौर में पानी बचाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है। पानी की बर्बादी न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारे भविष्य को भी खतरे में डालती है। इस लेख के माध्यम से हम यह समझेंगे कि पानी की टंकी की नियमित देखभाल और उसकी जांच क्यों जरूरी है।

पानी की महत्ता

पानी जीवन का आधार है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिना पानी के जीवन की कल्पना भी असंभव है। हमारे देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पीने के पानी की भारी कमी है। ऐसे में पानी की बर्बादी हमारे समाज के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है।

पानी की टंकी की देखभाल क्यों जरूरी है?

स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण: पानी की टंकी की सफाई न होने पर उसमें गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नियमित रूप से टंकी की सफाई करने से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं।

पानी की गुणवत्ता बनाए रखना: समय-समय पर पानी की टंकी की जांच करने से पानी की गुणवत्ता बनी रहती है। साफ और स्वच्छ पानी ही हमें बीमारियों से बचा सकता है।

पानी की बचत: कई बार टंकी में लीकेज हो जाता है, जिससे पानी बर्बाद होता है। नियमित जांच से हम इस लीकेज को समय रहते ठीक कर सकते हैं और पानी की बर्बादी रोक सकते हैं।

पानी की टंकी की जांच कैसे करें?

विजुअल निरीक्षण: नियमित रूप से टंकी का विजुअल निरीक्षण करें और देखें कि कहीं कोई दरार या लीकेज तो नहीं है।

साफ-सफाई: कम से कम हर छह महीने में टंकी की पूरी सफाई करें। इसके लिए टंकी को खाली करें, फिर उसे ब्रश से साफ करें और धुलकर साफ पानी से भरें।

फिल्टर की जांच: यदि आपकी टंकी में कोई फिल्टर लगा है, तो उसकी भी नियमित जांच करें और समय-समय पर उसे बदलें।

पानी बचाने के उपाय

नल को बंद रखें: जब पानी की आवश्यकता न हो, तो नल को बंद रखें।

लीकेज ठीक करें: कहीं भी लीकेज दिखे, तो उसे तुरंत ठीक करें।

जल संग्रहण: वर्षा जल संग्रहण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) को बढ़ावा दें।

पुनः उपयोग: जहाँ संभव हो, पानी का पुनः उपयोग करें, जैसे बगीचे में इस्तेमाल के लिए।

हम सभी का कर्तव्य है कि हम पानी की महत्ता को समझें और इसकी बर्बादी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें। पानी की टंकी की नियमित जांच और सफाई इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए, मिलकर पानी बचाएं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें।

indiangreenbuddy@gmail.com

इनसाइड

महिलाओं के लिए भी चमत्कारी है शिलाजीत, शरीर को मिलते हैं 5 गजब के फायदे, ऐसे करें सेवन

शिलाजीत को आमतौर पर पुरुषों के लिए शक्तिवर्धक पदार्थ माना जाता है, लेकिन यह महिलाओं के लिए भी वरदान साबित हो सकता है. महिलाएं सही तरीके से शिलाजीत का सेवन करें, तो कुछ ही समय में उनके शरीर में नई जान आ जाएगी और कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा. आज आपको बताएंगे कि शिलाजीत खाने से महिलाओं को कौन से बड़े फायदे हो सकते हैं और इसके सेवन का सही तरीका क्या है.

शिलाजीत सेहत के लिए बेहद लाभकारी पदार्थ होता है. आयुर्वेद में शिलाजीत को शरीर के लिए वरदान माना गया है. शिलाजीत पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाओं के शरीर में भी नई जान फूंक सकता है. यूपी

के अलीगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सरोज गौतम कहती हैं कि शिलाजीत कई पावरफुल पोषक तत्वों का खजाना होता है. इसका सेवन करने से महिलाओं की कमजोरी दूर हो सकती है. शिलाजीत शरीर में ताकत भर देता है. आयुर्वेद में शिलाजीत को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बताया गया है. यह महिला और पुरुष दोनों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है. जो लोग इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए शिलाजीत का सेवन हैरान करने वाले नतीजे दे सकता है. शिलाजीत में मौजूद औषधीय गुण फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं. कुछ लोग मानते हैं कि शिलाजीत सिर्फ पुरुषों की क्षमता बढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. यह महिलाओं के लिए भी उतना ही फायदेमंद है. शिलाजीत का इस्तेमाल डायबिटीज के मरीजों के इलाज में भी किया जाता है. डॉ. सरोज गौतम कहती हैं कि शिलाजीत का सेवन करने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. शिलाजीत एक रसायन होता है, जो वात, पित्त और कफ विकार में बेहद लाभकारी माना गया है. महिलाओं के लिए यह टॉनिक का काम करता है. हालांकि गर्भवती महिलाओं और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शिलाजीत नहीं देना चाहिए. हमारे शरीर की कोशिकाएं अगर मजबूत रहेंगी, तो लंबे समय तक किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. शिलाजीत खाने से इन कोशिकाओं को नई जान मिलती है और कोशिकाओं को क्षति को रोकने में मदद मिलती है. टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करने के लिए भी आयुर्वेद में शिलाजीत को असरदार माना गया है. शिलाजीत में मौजूद तत्व लोगों को कई गंभीर बीमारियों से राहत दिला सकते हैं. इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए लोग तमाम तरीके अपनाते हैं, लेकिन शिलाजीत इस काम को बखूबी कर सकता है. शिलाजीत को इम्यूनिटी बूस्टर माना जा सकता है. इस पदार्थ का सेवन करने से शरीर की अंदरूनी ताकत बढ़ती है और इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है. शिलाजीत का सेवन सही तरीके से किया जाए तो यह आपको बीमारियों से बचा सकता है. इससे आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं. अब सवाल उठता है कि शिलाजीत का सेवन किस तरह करना सही होता है. इस पर डॉ. सरोज गौतम कहती हैं कि शिलाजीत को दूध में मिलाकर पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. थोड़ा सा शिलाजीत अगर दूध में मिलाया जाए, तो यह दूध को शक्तिशाली पेय बना देता है. शिलाजीत को दिन या रात किसी भी वक्त सिरका और सूप में मिलाकर भी लिया जा सकता है. हालांकि शिलाजीत को कभी भी जूस में मिलाकर नहीं पीना चाहिए, वरना फायदा नहीं होगा.

रूमा पाल : भारत की पहली प्रसिद्ध महिला न्यायधीश

रूमा पाल (जन्म- 3 जून, 1941) भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायधीश रही हैं। उच्चतम न्यायालय के पूरे इतिहास में न्यायाधीश बनने वाली वे तीसरी महिला हैं, जो 3 जून, 2006 को सेवानिवृत्त हुईं। न्यायमूर्ति रूमा पाल उच्च न्यायपालिका में बहुत ईमानदार, विनम्र व विवेकशील मानी गयी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे किसी भी सामाजिक या व्यक्तिगत समारोह आदि में शामिल होने से बचती रहीं। यहाँ तक की अमेरिकी विश्वविद्यालय के बुलावे पर एक सम्मेलन में भाग लेने से भी इंकार कर दिया। एक न्यायाधीश के रूप में उन्हें किसी अन्य संस्था से अपनी यात्रा का टिकट लेना स्वीकार्य नहीं था। आज के दौर में सर्वोच्च न्यायपालिका में न सिर्फ़ न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया, बल्कि चयनित व्यक्तियों की ईमानदारी, सच्चाई और योग्यता भी बहस के घेरे में है, वहीं रूमा पाल न्यायपालिका में इसके उलट एक दुर्लभ व्यक्तित्व रहीं। केवल इसलिए नहीं कि वे एक महिला जज थीं, बल्कि इसलिए भी कि उनकी न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा ने इस संस्था को बहुत समृद्ध किया।

रूमा पाल का जन्म 3 जून, 1941 को हुआ था। उन्होंने विश्व-भारती विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की शिक्षा पूर्ण की थी। फिर नागपुर विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. तथा ऑक्सफ़ोर्ड से बैचलर ऑफ़ सिविल लॉ की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1948 में कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ की।

कॅरियर

न्यायमूर्ति रूमा पाल अगस्त, 1990 में कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनीं और जनवरी, 2000 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) में पदोन्नत किया गया। वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट में नये न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और तत्कालीन राष्ट्रपति के. आर. नारायणन के बीच विवाद हो गया। राष्ट्रपति नारायणन इस सूची के साथ न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन का नाम भी जोड़ना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं था। इस गतिरोध के चलते न्यायमूर्ति रूमा पाल, दोराई स्वामी राजू और योगेश कुमार सभरवाल की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में एक-दो माह का विलम्ब हुआ। सुप्रीम कोर्ट की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 28 जनवरी, 2000 को उन्हें नियुक्त किया गया। 3 जून, 2006 को रूमा पाल सेवानिवृत्त हो गयीं।

उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का निर्धारण न्यायाधीश के कार्यकाल की अवधि से होता है। यदि न्यायमूर्ति सभरवाल और रूमा पाल ने एक साथ शपथ ग्रहण किया होता तो वर्ष 2005 में दोनों ही मुख्य न्यायाधीश पद के लिए बराबर वरिष्ठता प्राप्त होते। इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय को 'टाइ-ब्रेकर' के लिए नाम के अक्षरों का क्रम या उच्च न्यायालय में उनके कार्यावधि के आधार पर यह निर्णय करना पड़ता कि मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा। वैसे उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सभरवाल की कार्यावधि रूमा पाल से अधिक थी, लेकिन अक्षरों के क्रम से न्यायमूर्ति रूमा पाल पहले आती थीं। इन न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह उच्चतम न्यायालय की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 28 जनवरी, 2000 को रखा गया। न्यायमूर्ति सभरवाल और दोराई स्वामी राजू के शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद रूमा पाल ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन वरिष्ठता क्रम में वह इन्हीं कुछ घंटों से पिछड़ गयीं और देश अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पाने से वंचित रह गया। योगेश कुमार सभरवाल और राष्ट्रपति के. आर. नारायणन की पसंद के. जी. बालाकृष्णन नियत समय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने।

ईमानदार छवि

वर्ष 2011 के वीएम तारकुंडे स्मृति व्याख्यान में रूमा पाल ने उच्च न्यायपालिका के चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाये और उच्च न्यायपालिका के सात गुनाहों की सूची प्रस्तुत की, जिनमें अपने साथी जजों के अनुचित कदमों पर परदा डालना, न्यायिक प्रक्रिया में अपारदर्शिता, दूसरों के लेखन की चोरी करना, पाखंड, अहंकारी व्यवहार, बेईमानी तथा सत्ताधारी वर्ग से अनुग्रह की आकांक्षा।

एक न्यायाधीश के रूप में रूमा पाल के व्यवहार को अनुकरणीय माना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक अमेरिकी विश्वविद्यालय द्वारा सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, चूंकि एक न्यायाधीश के रूप में वे किसी भी संस्था से अपनी हवाई यात्रा का टिकट नहीं लेना चाहती थीं। रूमा पाल की ईमानदारी और न्यायप्रियता उन्हें भारतीय न्यायपालिका में बहुत अलग व सम्माननीय स्थान प्रदान करती है।

रूमा पाल न्यायपालिका की गरिमा के प्रति बेहद संजीदा थीं। कोलकता के एमरी अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही के मुकदमे की सुनवाई हेतु गठित पीठ में वह भी शामिल थीं। जब रूमा पाल को मालूम हुआ कि कोलकाता उच्च न्यायालय में इनमें से कुछ चिकित्सकों के बचाव पक्ष के वकील उनके पति समरादित्य पाल थे, तो उन्होंने खुद को इस मुकदमे से अलग कर लिया।

सिगरेट निर्माता आइटीसी पर भारत सरकार ने 803 करोड़ रुपये आबकारी शुल्क जमा करने का आदेश दिया, तो इस आदेश के विरु द्ध आइटीसी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति रूमा पाल और पी. वेंकटरामा रेड्डी ने आइटीसी को राहत देने का निर्णय लिया। न्यायमूर्ति पाल ने आइटीसी के वकील को इस निर्णय का अंतिम प्रारूप इस शर्त पर पढ़ने दिया कि वे इसे अदालत कक्ष से बाहर लेकर नहीं जायेंगे। न्यायमूर्ति पाल की हिदायत के बावजूद आइटीसी के वकील इसे लेकर अदालत से बाहर चले आये और केवल कुछ ही मिनटों में मुंबई के शेयर बाज़ार में आइटीसी के शेयर मूल्य में अचानक उछाल आ गया। रूमा पाल ने आइटीसी के वकील की इस हरकत पर सख्त एतराज करते हुए अपना निर्णय वापस ले लिया और अंतिम निर्णय सुनाने की तारीख भी आगे बढ़ा दी।

उच्चतम न्यायालय में अपने कार्यकाल में रूमा पाल ने भारत सरकार द्वारा मोबाइल फोन की ख़रीद और सुविधा पर बिक्री कर लगाने के आदेश को निरस्त किया था। उन्होंने अपने एक निर्णय में पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों के न रहने की स्थिति में पत्नी द्वारा तलाक मांगने को उचित ठहराया था, जो एक बहुत ही प्रगतिशील निर्णय था।

40 की हो गई हैं आप, हेल्दी रहने के लिए डेली डाइट में शामिल करें 6 न्यूट्रिएंट्स, एक्सपर्ट ने बताए कारण

महिलाएं अक्सर अपने खानपान का ध्यान नहीं रखती हैं. अगर आपकी उम्र 40 की हो गई है तो आपको कुछ जरूरी पोषक तत्वों को डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. खासकर ओमेगा-3, प्रोटीन आदि से भरपूर चीजों का सेवन जरूर करें.

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है शरीर के अंग कमजोर होने लगते हैं. ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप कम उम्र से ही पोषक तत्वों से भरपूर चीजों का सेवन करें. साथ ही बढ़ती उम्र में भी उन सभी विटामिंस, मिनरल्स आदि को डाइट में शामिल करें, जो संपूर्ण सेहत के लिए जरूरी होते हैं. आपको बुजुर्गावस्था में बीमारियों से बचाए रखें. यह बात महिलाओं पर भी लागू होता है. खासकर, जब आपकी उम्र 40 पार हो रही हो तो आयरन, ओमेगा-3, प्रोटीन आदि से भरपूर चीजों का सेवन जरूर करें. अक्सर महिलाओं को पता नहीं होता है कि उन्हें 40 वर्ष की उम्र में कौन-कौन से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. आइए जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा से, जिन्होंने हाल ही में 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं के लिए कुछ आवश्यक न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक महत्वपूर्ण पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. जानें, उनके अनुसार आपको इस उम्र के पड़ाव में क्या-क्या डाइट में शामिल करना चाहिए.

1. प्रोटीन

न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा का कहना है कि महिलाओं को 40 वर्ष की उम्र में प्रोटीन का सेवन जरूर करना चाहिए. इस उम्र में मेनोपॉज होने के पहले कई तरह के हॉर्मोनल बदलाव भी होते हैं. कई बार शरीर में फैट बढ़ जाता है, लीन मसल मास में कमी आ जाती है, जो बाद में उनके दीर्घायु को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि आप प्रोटीन का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें. यह लीन मसल्स के नुकसान को रोकने में मदद कर सकता है.

5 आदतों को डेली लाइफ में शामिल करें महिलाएं, खूबसूरती में आएगा निखार, बन जाएंगी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी

2. बी विटामिन

40 से अधिक की उम्र वाली महिलाओं के लिए बी-विटामिन श्रृंखला वाले विटामिंस भी बेहद जरूरी हैं. आप जो भी खाती हैं, उस भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने या बनाने के लिए आपके शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया में ये बी-विटामिन काफी मदद करते हैं. साथ ही लाल रक्त कोशिकाओं को भी बनाने में मदद करते हैं.

3.कैल्शियम

जैसे-जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, उनकी हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखता है. कैल्शियम के सेवन से ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम किया जा सकता है. यह एक ऐसी बीमारी है, जिसमें हड्डियां भंगुर (brittle) हो जाती हैं. कैल्शियम की जरूरत मांसपेशियों के संकुचन, नर्व, हार्ट के कामकाज और अन्य जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं जैसे शरीर के अन्य बुनियादी कार्यों के लिए भी होती है. यदि आप अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम शामिल नहीं करती हैं तो शरीर आपकी हड्डियों से कैल्शियम चुराने लगता है, जिससे हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं.

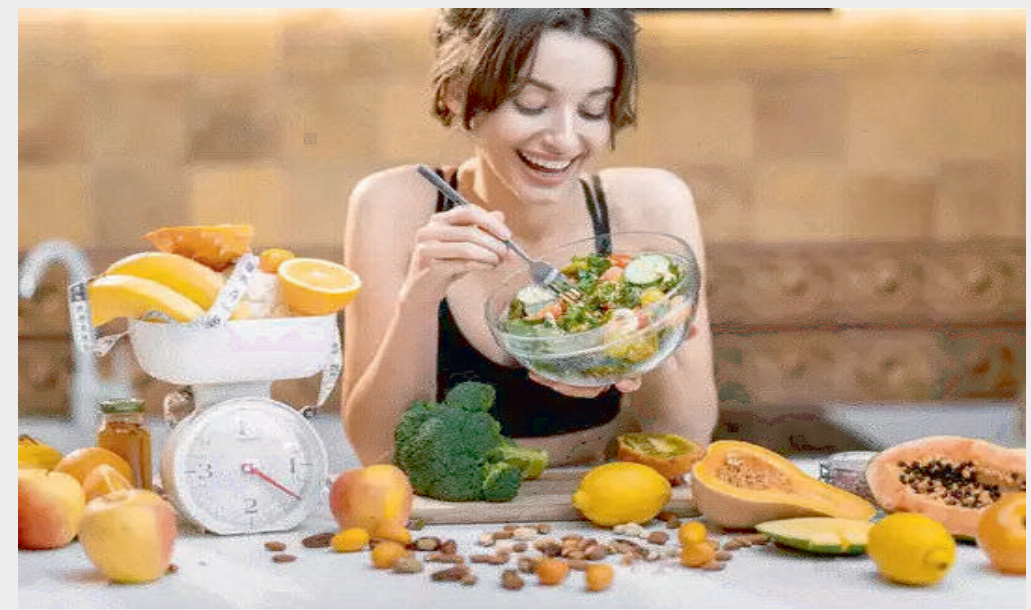

4. विटामिन डी

महिलाओं के लिए विटामिन डी भी बेहद जरूरी है. यह कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, इसलिए इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आप 40 की उम्र में आकर विटामिन डी भरपूर लें. साथ ही, विटामिन डी डायबिटीज, हृदय रोग सहित अन्य समस्याओं को कम करने में भी बेहद फायदेमंद होता है.

इसे भी पढ़ें: पुरुषों की तुलना में महिलाएं क्यों होती हैं ज्यादा एनीमिक? 9 लक्षण से करें पहचान, बिना दवा के भी दूर होगी समस्या

5. आयरन

क्या आप जानती हैं कि आपके शरीर को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है? यह एक ऐसा पदार्थ है, जो आपके लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है. 40 की उम्र ज्यादातर महिलाओं के लिए पेरिमेनोपॉज पीरियड का होता है. ऐसे में आयरन की कमी होने से आपको एनीमिया होने का जोखिम बढ़ सकता है. आयरन रिच डाइट आज से लेना शुरू कर दें.

6. ओमेगा-3 फैटी एसिड्स

माना जाता है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड्स कॉग्निशन और हार्ट की सेहत में सुधार करते हैं. ये लाभकारी फैट शरीर के कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को भी सामान्य और नियंत्रित करते हैं. तो आप यदि 40 की हो चुकी हैं तो बेहद जरूरी है कि आप ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स का सेवन करें.

कम उम्र में महिलाएं हो रही हैं हार्ट अटैक का शिकार

आजकल युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं ज्यादातर सामने आ रही हैं जिनमें खराब लाइफस्टाइल की आदतें और बढ़ता मोटापा या अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर जैसे कारण शामिल हैं.

आजकल की भागदौड़ भरी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के चलते हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ना एक आम समस्या बन गई है. यह एक ऐसी गंभीर स्थिति है जो अक्सर लोगों की जान ले सकती है. हार्ट अटैक के सबसे सामान्य लक्षण सीने में दर्द या दबाव महसूस होना होते हैं. यह समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है. एक्सपर्ट्स की माने तो यह समस्या कम उम्र के लोगों और खासकर महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिल रही है. यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि वृद्धो में दिल के दौरे के दर में कमी आयी है और यही संख्या युवाओ में बढ़ी है. इसमें भी खासकर महिलाओं को हार्ट अटैक ज्यादा प्रभावित कर रहा है.

महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या होने के कारणों में हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज और मोटापा आदि हो सकते है. आइए जानते हैं

महिलाओं में हार्टअटैक की समस्या होने के कारण

हाई ब्लड प्रेशर

हॉपकिंस मेडिसिन डॉट ओआरजी के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर के कारण महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल सकती है. हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं. लाइफस्टाइल की कुछ गलत आदतों के कारण या महिलाओं में गर्भावस्था और बर्थ कंट्रोल पिल्स हाई ब्लड प्रेशर होने के रिस्क को बढ़ा देती है अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के साथ-साथ स्मोक भी करती हैं तो इससे ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना अधिक हो जाती है.

हाई कोलेस्ट्रॉल

एस्ट्रोजन महिलाओं को एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाने का काम करता है लेकिन मेनोपॉज़ जैसी स्थिति के बाद एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है और हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना अधिक हो जाती है. हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण महिलाओं में हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है.

स्मोकिंग

स्मोकिंग करने से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है. ऐसे में स्मोकिंग करने वाली महिलाओं में स्मोकिंग करने वाले पुरुषों की तुलना में हार्ट डिजीज विकसित होने का खतरा और ज्यादा अधिक होता है.

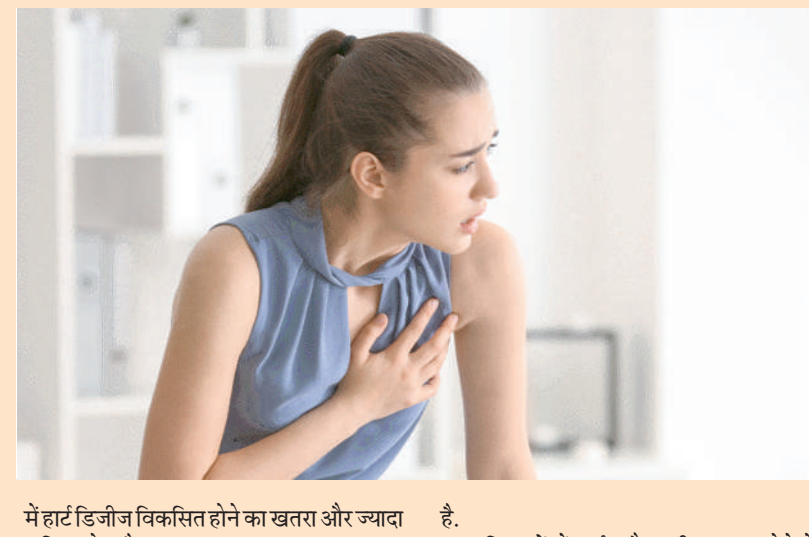

निकोटीन आपकी बॉडी के सभी भागों जैसे हार्ट और ब्लड वेसल्स से लेकर आपके हार्मोंस, मेटाबॉलिज्म और ब्रेन तक, को प्रभावित कर सकता है.

महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या होने के अन्य कारणों में डायबिटीज, मोटापा, जेनेटिक्स हार्ट समस्याएं, उम्र, अत्यधिक शराब का सेवन और खराब लाइफस्टाइल शामिल हो सकते हैं.

2 जून को जेल,केजरीवाल फेल,कांग्रेस ने किया खेल

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। लोकसभा चुनाव 2024 एग्जिट पोल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है।वहीं कांग्रेस की लुटिया डूबने के साथ ही आम आदमी पार्टी भी मोदी मैजिक की आंधी में उडती दिखाई दे रही है। हालांकि आप पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक बार फिर 2 जून की रोटी जेल में खाने को मिलने जा रही है। इस 2 जून की जेल को रोकने के लिए केजरीवाल ने तमाम कोर्ट की कसरतें पूरी करने के बावजूद आखिर रविवार को जेल में समर्पण करना पडा। हालांकि अंत तक केजरीवाल ने अपनी बीमारी और बॉडी टेस्ट की आढ में एक हफ्ते की जमानत की कोर्ट से गुहार लगाने के बावजूद कोर्ट ने कोई ढील नहीं दी। और 21 दिन जेल से बाहर आने के बाद फिर जेल में पहुंच गए। हालांकि केजरीवाल ने 21 दिन की मिली जमानत के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, के तीनों सूबे में जमकर रैली,रोड शो चुनाव प्रचार किया। लेकिन कांग्रेस के पंजे ने झाड़ू को कसकर पकडा और तिनके बिखरने नहीं दिए पर केजरीवाल के किये पर पानी जरूर फेर दिया। न्यूज -18 एक्जिट पोल रिजल्ट -2024 में दिल्ली की 7 सीटों में से 5-7 सीट बीजेपी सकती है।इसमें भी दोनों सीटो पर कांग्रेस के पंजे के उम्मीदवार की जीत की संभावना है। जबकि आम आदमी पार्टी को सीफर सीट दिखाई गई है। इसके अलावा हरियाणा की 10 सीटों में से 5-7 सीटें बीजेपी के खाते में तो, 3-5 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। जबकि यहां भी आम आदमी पार्टी का खाता भी खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह पंजाब में 13 सीटों में से 2-4 सींटे एनडीए के खाते में जा सकती है।जबकि यहां 8-10 सीटो पर कांग्रेस पंजे का कब्जा हो सकता है। यहां आम आदमी पार्टी का 0 से 1 सीट ही मिलने की संभावना है। इन सारी जुगलबंदी के बावजूद आप और कांग्रेस गठबंधन से उल्टे दिल्ली,हरियाणा और पंजाब में नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इससे तो साफ है कि कांग्रेस का दिमागी खेल ,अरविंद केजरीवाल को जेल, और आम आदमी पार्टी हुई फेल ,का बेमेल रिश्ता जल्द ही धाराशाही होता दिख रहा है।

गठबंधन की जीत का अनुमान है।वहीं इंडिया गठबंधन को 02 सीटों पर जीत हांसिल हो

दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी- एलजी, क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन ?

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल के दोबारा से रविवार को तिहाड जेल में जाने के बाद, सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने और जेल से ही सरकार चलाने की घोषणा किए जाने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सेक्सेना ने दो टूक शब्दों में कहा है कि दिल्ली की सरकार किसी भी सूरत में जेल से नहीं चलेगी। उन्नाहोने कहा कि राजधानी दिल्ली का कोई भी कार्य रूकने नहीं दिया जाएगा।

एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में यदि संवैधानिक संकट वाली स्थिति पैदा होती है तो दिल्ली का काम रूकने नही दिया जाएगा।

उन्होने कहा कि अगर काम में बाधा पैदा करने की कोशिश की जाएगी, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एलजी के इन संदेशों से तो लगता है कि दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है?

एलजी ने अपने कार्यो को गिनाते हुए कहा कि जी-20 के दौरान दिल्ली को संवारा ,5000 से ज्यादा सीसीटीवी लगवाए।100 से ज्यादा,मूर्तियां लगवाई, जनसुविधाओ में सुधार के तहत अनाधिकृत कालोनी में जल निकासी,सीवरेज,,पानी ,सडक बनवाने,से लेकर यमुना नदी घाट की सफाई, सौंदर्यीकरण ,के साथ ही पुरातत्व इमारतों के सौंदर्यकरण , जीर्णोद्धार, या कायाकल्प किया गया।इसके अलावा लैंडफील्ड, साइटों से कूडा उठवाना भी शामिल है। इसके अलावा दिल्ली के गांवों में ढांचागत विकास के तहत 995 करोड रूपये बाकायदा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को दिए गए। नरेला में जमीने डीडीए को आवंटन कर दी गई हैं। जहां यूनिवर्सिटीज, संस्थान, परिवहन आदि के विकास कार्य किए जा रहे हैं। एलजी वीके सक्सेना ने बडा ऐलान करते हुए कहा कि अभी तक दिल्ली केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है। उसे भी जल्द ही लागू किया जाएगा। एलजी के इस दिए संदेशों से तो ये ही जाहिर हो रहा है कि चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद पर अमल किया जा सकता है

'मैं भी फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं', तिहाड़ में सरेंडर करने से पहले बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल

परिवहन विशेष न्यूज

अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर करने से पहले केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी (AAP Delhi Office) के कार्यालय में संबोधित किया। जहां उन्होंने भाजपा सरकार निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है।

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर करने से पहले केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी (AAP Delhi Office) के कार्यालय में संबोधित किया। जहां उन्होंने भाजपा सरकार निशाना साधा।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है। बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने तानाशाही के लिए आवाज उठाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद एक इंटरव्यू में कबूल कर लिया कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सुबूत नहीं है।

मुझे अनुभवी चोर कहा तो बताओ...

उन्होंने मुझे अनुभवी चोर कहा। अरे भई अगर आपके पास कोई सुबूत ही नहीं है तो दिल्ली के इतने भारी बहुमत वाले मुख्यमंत्री को बिना बात जेल में डाल दिया। यही तानाशाही है, इसी के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। हम भगत सिंह के चेले हैं। वो देश को आजाद कराने के लिए जेल गए, मैंने देश बचाने के लिए जा रहा हूं। भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, मैं भी फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए है।

कोर्ट का जताया आभार

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी। मैं कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इन 21 दिनों में मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया, लगातार सभी पार्टियों के देशभर में देश बचाने को प्रचार किया। आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं, पहले देश है।

केजरीवाल ने कहा कि चार तारीख को भी मंगलवार है। भला करेंगे बजरंग बली, इनका नाश करेंगे। मैं हनुमान मंदिर में प्रार्थना करके आया हूं। उनकी कृपा जरूर बनी रहेगी। कल एग्जिट पोल आए हैं, सभी फर्जी हैं। इनमें से एक भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं होने वाला

कहा जा रहा है कि इन्होंने ईवीएम घोटाला कर दिया। मैं सभी पार्टियों के एजेंटों से कहना चाहूंगा कि मतगणना केंद्र को आखिर तक न छोड़ें। अगर आपका उम्मीदवार हार भी रहा है तो लास्ट तक रूकें। ईवीएम चेक कराकर ही निकलें।

जल संकट: दिल्ली में खाली बाल्टियां लेकर पानी को भटक रहे लोग, कई इलाकों में किल्लत

दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत जारी है। लोग पानी के टैंकरों के पीछे खाली बाल्टियां लेकर भटक रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में लोग पानी की बाल्टियां भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। दिल्ली के ओखला चाणक्यपुरी के संजय कैंप इलाके और गीता कॉलोनी में पानी की भारी किल्लत है।

नई दिल्ली। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत जारी है। लोग पानी के टैंकरों के पीछे खाली बाल्टियां लेकर भटक रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में लोग पानी की बाल्टियां भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं।

दिल्ली के ओखला, चाणक्यपुरी के संजय कैंप इलाके और गीता कॉलोनी में पानी की भारी किल्लत है। एक वीजियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चलते हुए पानी के टैंकर पर चढ़ते हुए लोगों को देखा जा सकता है। जबकि कई अन्य लोग बाल्टी और पाइप लेकर उसके साथ दौड़ रहे हैं।

इस बीच दिल्ली में जल संकट पर बोलते हुए जल मंत्री आतिशी ने कहा कि गर्मी के कारण पानी की मांग बढ़ गई है और दूसरी ओर यमुना में जल स्तर कम हो गया है। पिछले साल वजीराबाद तालाब में 674.5 फीट पानी था। इतने अनुरोधों के बावजूद केवल 671 फीट पानी छोड़ा गया है। वजीराबाद बैराज में पानी का स्तर कम होने के कारण सभी जल उपचार संयंत्र प्रभावित हो रहे हैं। हमने हरियाणा और यूपी सरकार से और पानी छोड़ने का अनुरोध किया है।

दिल्ली सरकार ने 31 मई को पड़ोसी राज्य हरियाणा से तत्काल अतिरिक्त पानी प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि उत्तर भारत, खासकर दिल्ली में चल रही भीषण गर्मी के कारण दिल्ली के लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वह याचिका दायर करने के लिए बाध्य है।

याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार को तत्काल पानी छोड़ने के लिए निर्देश दिया जाए। जल संकट के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 30 मई को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति की निगरानी के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा।

डीयू एडमिशन में एससी/एसटी व ओबीसी छात्रों से जाति प्रमाण पत्रों के लिए अंडरटेकिंग लिए जाने की फोरम ने कुलपति से मांग की

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र - 2024-25 के लिए अपनी अंडरग्रेजुएट (यूजी) एडमिशन पॉलिसी लॉन्च कर दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूजी एडमिशन पोर्टल ₹कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस)₹ की लॉन्चिंग के साथ ही विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिलों के पहले फेज की शुरूआत हो गई है । इस साल 71 हजार छात्रों को एडमिशन दिया जायेगा जिसमें भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार एससी --15 प्रतिशत , एसटी --7 :5 प्रतिशत व ओबीसी -- 27 प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान किया गया है । इसके साथ ही स्कूल ऑफ ओपनलर्निंग (एसओएल) और एनसीवेब के लिए भी दाखिला संबंधी सभी जानकारी दी गई लेकिन गत वर्ष की भांति इस साल भी एससी/एसटी व ओबीसी छात्रों के जाति प्रमाण पत्र ना होने पर अंडरटेकिंग लेकर प्रोविजनल एडमिशन करने संबंधी जानकारी नहीं दी गई। छात्रों के पास एससी/एसटी व ओबीसी सर्टिफिकेट ना होने पर उससे अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाने के लिए कितना समय दिया गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया गया। जबकि पिछले साल भी आरक्षित श्रेणी के छात्रों की सीटें इसलिए खाली रह गई थीं कि उनका जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाया था। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने डीयू कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर एससी/एसटी व ओबीसी छात्रों के जाति प्रमाण पत्र न होने पर उससे अंडरटेकिंग लेकर प्रोविजनल एडमिशन किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि अन्य विश्वविद्यालयों में अंडरटेकिंग के माध्यम से प्रोविजनल एडमिशन दिया जाता है ।

फोरम के चेयरमैन डॉ.हंसराज सुमन ने डीयू कुलपति से मांग की है कि जिनके पास ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) जाति प्रमाण पत्र 31 मार्च 2024 के बाद का नहीं है उन छात्रों से अंडरटेकिंग लेकर प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाए। उन्होंने बताया है कि जिन छात्रों के पास सीयूईटी फॉर्म भरने से पूर्व पुराना जाति प्रमाण पत्र था, अभी उन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र नवीनीकरण कराने के लिए दिया है। सरकारी ऑफिस समय पर जाति प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दे पाता है। इसलिए एडमिशन के समय उन छात्रों को जाति प्रमाण पत्र के न होने पर रोका न जाए बल्कि उन छात्रों से अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाकर एडमिशन दे दिया जाए ताकि उसका साल खराब न होने पाए।

डॉ.सुमन ने पत्र में यह भी लिखा है कि फोरम मांग करता है कि शिक्षा मंत्रालय व यूजीसी समय-समय पर केंद्र सरकार की आरक्षण नीति संबंधी जानकारी सर्कुलर के माध्यम से छात्रों/शिक्षकों/कर्मचारियों के बीच जारी करता रहा है ताकि इन सुविधाओं का लाभ आरक्षित वर्गो को मिले यह जानकारी विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान को अपनी वेबसाइट

पर अपलोड करना होता है लेकिन कोई भी कॉलेज एससी/एसटी व ओबीसी छात्रों के प्रवेश संबंधी आंकड़े और विषयवार बची आरक्षित वर्ग की सीटों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है। ना ही वे पिछले वर्ष आरक्षित वर्ग की खाली रह गई सीटों का ब्यौरा अपलोड करते हैं। इसी तरह ना ही वे आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के खाली पदों की संख्या, बैकलॉग पदों का ब्यौरा आदि को वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। जबकि यूजीसी हर साल एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व व बीच-बीच में आरक्षण संबंधी जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए सर्कुलर व निर्देश जारी करती है। उन्होंने पुनः यह मांग की है कि शिक्षा मंत्रालय व यूजीसी के आरक्षण संबंधी जारी किए गए सर्कुलर को लागू करने का सख्त निर्देश दिया जाए। ताकि संविधान प्रदत्त आरक्षण नियमों का लाभ सभी शिक्षकों /कर्मचारियों /छात्रों को मिल सकें। आरक्षित श्रेणी के छात्रों की सीटें क्यों खाली रह जाती हैं - डॉ. सुमन ने बताया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कारण एससी/एसटी व ओबीसी कोटे की सीटों में इजाफा हुआ है और हर साल आरक्षित वर्ग की सीटों पर ज्यादा छात्र विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं। उन्होंने आगे बताया है कि एडमिशन के पहले, दूसरे राउंड में आरक्षित वर्ग के बहुत कम छात्र दाखिला ले पाते हैं। यदि कॉलेज और विश्वविद्यालय के विभाग आरक्षित वर्ग की सीटों का कट-ऑफ कम रखें तो आरक्षित वर्ग के छात्र प्रवेश ले पाएंगे। होता यह है कि आरक्षित वर्ग की सीटें खाली पड़ी रहती हैं। जब इन सीटों को भरने के लिए प्रशासन का दबाव आता है तब जाकर कट-ऑफ कम की जाती है यह अक्सर सितम्बर और अक्टूबर के महीने में होता है तब तक ये छात्र कहीं दूसरे प्राइवेट विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रवेश ले चुके होते हैं। परिणामस्वरूप कई स्पॉट राउंड निकालने के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं । उन्होंने विश्वविद्यालय को सुझाव दिया है कि जब तक एससी/एसटी व ओबीसी कोटे की सीटें न भरे तब तक विश्वविद्यालय को आरक्षित वर्ग के प्रवेश संबंधी अंकों का प्रतिशत कम रखना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय आरक्षित वर्ग के कट ऑफ के अंकों को कम नहीं करेगा तो ये सीटें हमेशा खाली ही रह जाएंगी।

डॉ. हंसराज सुमन
चेयरमैन—फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस

राजधानी में इन सात जगहों पर होगी मतों की गिनती, खुलेगा 162 उम्मीदवारों के भाग्य का पिटारा

परिवहन विशेष न्यूज

सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वैसे तो दोपहर तक सातों सीटों पर चुनाव के नतीजों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ईवीएम से वोटों की गिनती और अंत में वीवीपैट से वोटों के मिलान की प्रक्रिया के मद्देनजर शाम चार बजे तक फाइनल परिणाम घोषित होने की संभावना है। दिल्ली में 25 मई को कुल 13641 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए थे।

नई दिल्ली। दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार को सात जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी। इसके दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है। सुबह आठ बजे ईवीएम खुलेगी। इसके करीब आधे घंटे बाद सुबह साढ़े आठ बजे से दिल्ली में चुनाव नतीजों का रुझान मिलना शुरू हो जाएगा।

इसके साथ ही भाजपा व आइएनडीआइए (कांग्रेस व आम आदमी पार्टी) के प्रत्याशियों सहित दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए चुनावी मैदान उतरे 162 उम्मीदवारों के भाग्य का पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा।

शाम चार बजे तक परिणाम की घोषणा

सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वैसे तो दोपहर तक सातों सीटों पर चुनाव के नतीजों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ईवीएम से वोटों की गिनती और अंत में वीवीपैट से वोटों के मिलान की प्रक्रिया के मद्देनजर शाम चार बजे तक फाइनल परिणाम घोषित होने की संभावना है।

दिल्ली में 25 मई को 2623 मतदान स्थलों पर बने कुल 13,641 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए थे। इस दौरान कुल 58.70 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसके बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में दो स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है।

प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में दस विधानसभा क्षेत्र

दिल्ली के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में दस विधानसभा क्षेत्र हैं। वोटों की गिनती विधानसभा क्षेत्र के अनुसार होगी। हर विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती के लिए अलग-अलग टेबल की व्यवस्था होगी।। इसलिए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम एक साथ खुलेगी। बताया जा रहा है कि 15 से 18 राउंड में वोटों की गिनती पूरी होगी। सभी मतगणना केंद्रों में एक मीडिया सेंटर होगा जहां हर राउंड के मतगणना की जानकारी दी जाएगी।

प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के 50 वीवीपैट की पर्ची की होगी गिनती

सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केंद्रों के वीवीपैट की पर्ची का ईवीएम के वोटों से मिलान होगा। इस तरह दिल्ली में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के 50 वीवीपैट की पर्ची की गिनती कर ईवीएम के वोटों से मिलान किया जाएगा।

दिल्ली के सातों संसदीय क्षेत्रों के लिए बने मतगणना केंद्र

चांदनी चौक- एसकेवी, भारत नगर
उत्तर-पूर्वी दिल्ली- आइटीआई, नंदनगरी
पूर्वी दिल्ली- राष्ट्रमंडल खेल गांव, खेल परिसर
नई दिल्ली- अटल आदर्श बालिका विद्यालय, गोल मार्केट
उत्तर-पश्चिम दिल्ली- डीटीयू, शाहबाद, दौलतपुर
पश्चिमी दिल्ली- एनएसयूटी, द्वारका
दक्षिण दिल्ली- जीजाबाई महिला आइटीआइ, सिरी फोर्ट

एग्जिट पोल से गदगद दिल्ली BJP के नेता, 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दिया 2000 किलो लड्डू बनाने का ऑर्डर

परिवहन विशेष न्यूज

मुंडका से पार्षद गजेंद्र दराल ने बताया कि दिल्ली में 100 प्रतिशत भाजपा जीत रही है। इसलिए उन्होंने 1111 किलो लड्डू का आर्डर हलवाई को दिया है। मतगणना केंद्र के बाहर से ही जश्न शुरू हो जाएगा। लोगों को लड्डू बांटे जाएंगे और जगह-जगह मीठे पानी की छबील लगवाई जाएंगी। रोड शो निकालकर सभी लोगों के साथ खुशी साझा की जाएगी।

पश्चिमी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं।इसलिए मतगणना से पहले ही जश्न की तैयारी शुरू कर दी गई हैं। कोई जीत के जश्न के लिए पटाखों का इंतजाम कर रहा है तो कोई रोड शो के लिए मैप बना रहा है। कोई लड्डू के एडवांस बुकिंग कर रहा है तो कोई हलवाई बुलाकर अपने सामने लड्डू बनवा रहा है।

मुंडका से पार्षद गजेंद्र दराल ने बताया कि दिल्ली में 100 प्रतिशत भाजपा जीत रही है। इसलिए उन्होंने 1111 किलो लड्डू का आर्डर हलवाई को दिया है। मतगणना केंद्र के बाहर से ही जश्न शुरू हो जाएगा। लोगों को लड्डू बांटे जाएंगे और जगह-जगह मीठे पानी की छबील लगवाई जाएंगी। रोड शो निकालकर सभी लोगों के साथ खुशी साझा की जाएगी।

10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दो हजार किलो लड्डू का ऑर्डर

वहीं द्वारका में भाजपा किसान मोर्चा पूर्व मंडल उपाध्यक्ष संजय चौधरी व पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश ध्यानी ने बताया कि पश्चिमी दिल्ली की दस विधानसभा क्षेत्र के लिए दो हजार किलो लड्डू का आर्डर दिया गया है। इसके लिए सुल्हाकुल मंदिर परिसर में हलवाई बैठा दिया गया है। कुछ लड्डू बन गए हैं और कुछ सोमवार रात तक बनकर तैयार हो जाएंगे।

मंगलवार को द्वारका स्थित मतगणना केंद्र के बाहर लड्डू बांटे जाएंगे। इसके बाद एनएसयूटी से द्वारका मोड, तिलक नगर पानी की टंकी, जेल रोड, डाबरी से द्वारका होते हुए अमराही गांव के मंदिर में भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत मत्था टेकेंगी।

गाजियाबाद में मतगणना स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, धारा 144 लागू; इन चीजों पर रहेगी रोक

परिवहन विशेष न्यूज

चार जून को गोविंदपुरम अनाज मंडी में मतगणना होगी। इसके चलते आसपास ड्रोन उड़ाने सहित कई चीजों पर पाबंदी रहेगी। धारा 144 का आदेश पांच जून की आधी रात तक लागू रहेगा। चार जून के लिए पुलिस ने 17 बिंदुओं पर यह गाइडलाइन जारी की है। पुलिस की गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु यह हैं। थाना कविनगर क्षेत्र को नो ड्रोन जोन/अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है।

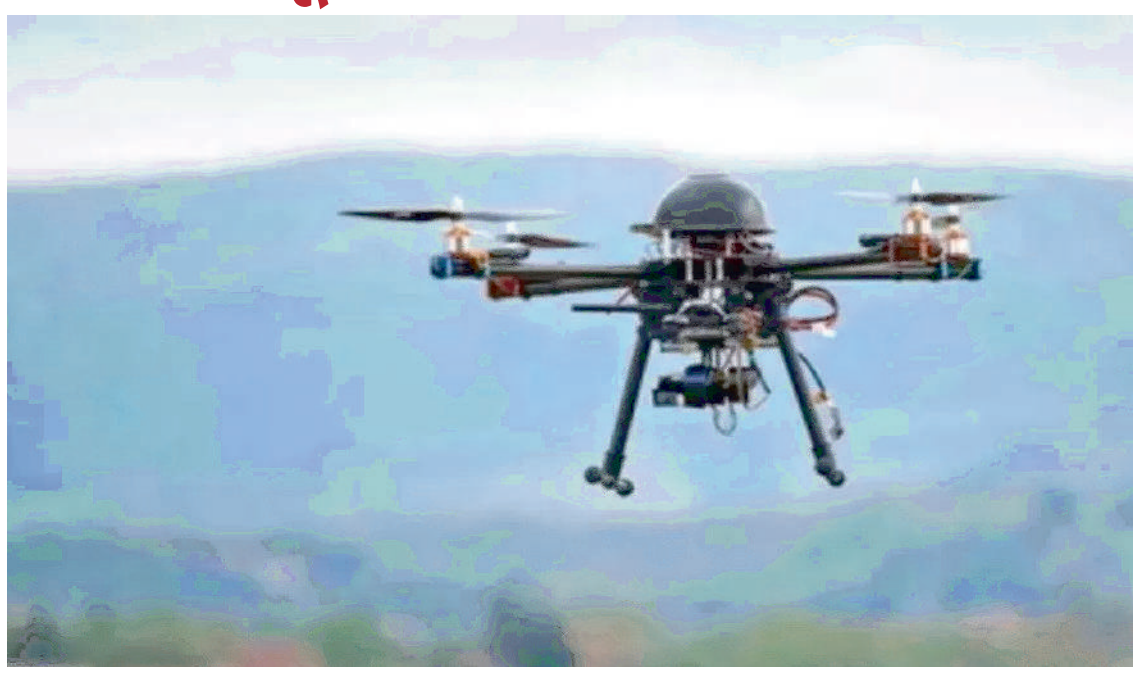

गाजियाबाद। चार जून को हापुड़ रोड स्थित गोविंदपुरम अनाज मंडी में मतगणना के दिन कविनगर थानाक्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी ने मतगणना के चलते धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है।

17 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी

इसके तहत मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर का प्रयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। धारा 144 का आदेश पांच जून की आधी रात तक लागू रहेगा।

चार जून के लिए पुलिस ने 17 बिंदुओं पर यह गाइडलाइन जारी की है। पुलिस की गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु यह हैं। मतगणना के चलते थाना कविनगर क्षेत्र को नो ड्रोन जोन/अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है।

कम्यूनिकेशन डिवाइस ले जाने पर पाबंदी

मतगणना में मीडियाकर्मी या अन्य व्यक्ति एवं संगठन को प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है तो कविनगर थाने में ड्रोन एवं ड्रोन ऑपरेटर की जानकारी देनी है।

डीसीपी सिटी से इसकी अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति उड़ने वाली प्रतिबंधित वस्तुओं को नष्ट कर दिया जाएगा। मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन समेत अन्य कम्यूनिकेशन डिवाइस ले जाने पर पाबंदी है।

फेक न्यूज फैलाने वालों पर रहेगी नजर

मतगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के कार्य में अवरोध पैदा नहीं करेंगे उन्हें सहयोग करेंगे।

मतगणना के दिन किए गए ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करेंगे।

मतगणना में आने वाले समस्त पार्टी के प्रत्याशी एवं कार्यकर्ता वाहन तय किए गए स्थान पर ही खड़ा करेंगे।

फेक न्यूज सोशल मीडिया पर नहीं फैलाई जाएगी, पुलिस ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई करेगी

राजनीतक दल के नेता या समर्थक किसी भी जाति विशेष या धार्मिक आधार पर टिप्पणी नहीं करेंगे

मतगणना स्थल के आसपास धरना प्रदर्शन या विजय जुलूस पर पाबंदी

बिना अनुमति सावर्जजनिक कार्यक्रम पर पाबंदी। कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी कराएंगे।

मतगणना स्थल पर असलहे का प्रदर्शन एवं लेकर जाने पर पाबंदी।

गाली-गलौज का विरोध करने पर युवक को मारा चाकू, शोर सुनकर दौड़े लोग

अमर विहार कॉलोनी में शनिवार देर रात गाली–गलौज का विरोध करने पर नशे में धुत पड़ोसी ने युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। स्वजन ने घायल को दिल्ली जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया हैं जहां उसका उपचार चल रहा है। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार भास्कर वर्मा ने बताया की पीड़ित से शिकायत लेकर जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

लोनी। लोनी बॉर्डर क्षेत्र अमर विहार कॉलोनी में शनिवार देर रात गाली-गलौज का विरोध करने पर नशे में धुत पड़ोसी ने युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। स्वजन ने घायल को दिल्ली जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया हैं जहां उसका उपचार चल रहा है। पीड़ति स्वजन ने थाने पहुंच कर लिखित शिकायत दर्ज करवाई है।

अमर विहार कॉलोनी के देवेन्द्र पुत्र राजकुमार उम्र 45 वर्ष ने बॉर्डर थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि पड़ोस में रहने वाले ललित नशा करके आया और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा, जब गाली का विरोध किया तो चाकू निकालकर हमला कर पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया।

शोर सुनकर स्वजन निकल कर आए और उसे उपचार के लिए दिल्ली जीटीबी अस्पताल ले गए। जहां उसका उपचार चल रहा है। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार भास्कर वर्मा ने बताया की पीड़ित से शिकायत लेकर जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा में स्कूलों की मनमानी, बीएसए के सत्यापन को फर्जी बताकर नहीं दे रहे प्रवेश

अभी जारी तीनों लॉटरी के तहत प्रवेश की अंतिम तिथि बीत चुकी है लेकिन जिले में केवल 43 प्रतिशत ही छात्रों को ही प्रवेश मिल पाए हैं। प्रवेश न लेने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से वर्ष दर वर्ष उनकी मनमानी बढ़ती जा रही है। आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन के बाद बीएसए विभाग द्वारा सभी अहर्ता प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है।

नोएडा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश देने में निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। स्कूल बेसिक शिक्षा विभाग के सत्यापन को ही गलत बता प्रवेश से अपना पला झाड़ रहा है। परेशान अभिभावक बीएसए कार्यालय और स्कूल के बीच चक्कर काट रहे हैं। अभी जारी तीनों लॉटरी के तहत प्रवेश की अंतिम तिथि बीत चुकी है, लेकिन जिले में केवल 43 प्रतिशत ही छात्रों को ही प्रवेश मिल पाए हैं। प्रवेश न लेने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से वर्ष दर वर्ष उनकी मनमानी बढ़ती जा रही है। जिले में बीते वर्ष भी लगभग 70 प्रतिशत छात्रों के ही प्रवेश हो पाए थे।

अब तक 2100 सीटों पर ही हो पाया प्रवेश : इस सत्र में अब तक तीन लॉटरी जारी हो चुकी है। चौथी के लिए आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हुई है। विभाग ने तीनों चरण में 11,303 आवेदनों के सत्यापन के बाद 4786 सीट आवंटित की थी। अब तक इनमें से लगभग 2100 सीटों पर ही प्रवेश हो पाया है।

प्रतिबंध लगने के पहले दिन नियम धड़ाम, साथ-साथ बिके पान मसाला और तंबाकू

आयुक्त खाद्य सुरक्षा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एक जून से एक दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की साथ बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए। प्रचार प्रसार की कमी कहें या तंबाकू और पान मसाला बेचने वाले दुकानदारों की दादागिरी प्रतिबंध के पहले दिन अधिकांश दुकानों पर पान मसाला और तंबाकू की एक ही दुकान पर साथ–साथ खुलेआम बिक्री होती नजर आई।

गाजियाबाद। आयुक्त खाद्य सुरक्षा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एक जून से एक दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की साथ बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए। प्रचार प्रसार की कमी कहें या तंबाकू और पान मसाला बेचने वाले दुकानदारों की दादागिरी प्रतिबंध के पहले दिन अधिकांश दुकानों पर पान मसाला और तंबाकू की एक ही दुकान पर साथ-साथ खुलेआम बिक्री होती नजर आई। इसे लेकर दैनिक जागरण संवाददाता शाहनवाज अली की पड़ताल करते हुए एक रिपोर्ट।

शहर के घंटाघर पर एक दुकानदार के यहां जब पान मसाला और तंबाकू मांगा गया तो उसने झट से दोनों चीजें निकालकर हाथ में दे दी। उससे पूछा गया कि क्या उसे नहीं पता कि दोनों की एक साथ एक दुकान पर बिक्री को लेकर पाबंदी लगा दी गई है। वह बोला कि अभी उसे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उसके पास काफी माल है उसे नाले में थोड़े ही फेंका जाएगा। अगर ऐसा कोई कानून बना है तो कोई बताएगा तो आगे से नहीं बेचेंगे।

दुकानदार बिना किसी झिझक के पाउच दिए

इसी तरह वसुंधरा सेक्टर- 12 में पान के खोखे पर पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति ने आकर पान मसाला और तंबाकू मांगा। दुकानदार ने बिना किसी झिझक के उसे दोनों अलग-अलग पाउच दे दिए। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने दोनों पाउच फाड़कर एक दूसरे पाउच में मिलाने के बाद हिलाकर मुंह में डालकर आगे बढ़ गया। दुकानदार से जब तंबाकू और पान मसाले की एक साथ बिक्री पर पाबंदी के बारे में पूछा तो उसने जानकारी होने से इनकार कर दिया।

खुलेआम पान मसाला की लड़ियां टंगी दिखी

वसुंधरा सेक्टर पांच में भी दुकान पर ऐसे ही सामने खुलेआम पान मसाला की लड़ियां टंगी हुई दिखाई दी। जब उससे पान मसाला के साथ तंबाकू मांगा गया तो उसने पूछा कितने दूं। इसके बाद पाबंदी वाली बात उसे भी बताई गई तो उसने कहा कि इस तरह के कानून बनते रहते हैं। यह कोई न बेचना छोड़ेगा और न खरीदना। जो लोग इसे खाते हैं उन्हें इसकी बहुत बुरी लत है, जो किसी सूरत में इसे खाना नहीं छोड़ सकते। फिर इसे अलग दुकानों पर बेचने की क्या जरूरत।

ऐसे होगी कार्रवाई

एक ही दुकान पर पान मसाला व तंबाकू पाउच बेचते पकड़े जाने पर पहले नोटिस, फिर मुकदमा व सुनवाई के बाद जुर्माना की कार्रवाई होगी। अधिकतम दो लाख रुपये तक जुर्माना होगा।

पान मसाला व तंबाकू एक साथ बेचने पर जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। काफी संख्या में दुकान और खोखों पर पान मसाला व तंबाकू के पाउच एक साथ बिक रहे हैं। इन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें कार्रवाई करेंगी।

- अरविंद कुमार, जिला अभिहित अधिकारी

नहर में डूबने किशोर की मौत, साथी को बचाया

सुमित शुक्रवार रात को अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए मुरादनगर स्थित गंगनहर घाट पर आया था। रात को करीब नौ बजे गहरे पानी में जाने के कारण किशोर व उसका दोस्त डूबने लगे। दोनों की आवाज सुनकर गोताखोरों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। गोताखोरों ने साथी को तो बचा लिया लेकिन सुमित पानी में डूब गया।

मुरादनगर। गंगनहर घाट पर नहाने के दौरान एक 17 वर्षीय किशोर की नहर में डूबने से मौत हो गई जबकि उसके साथी को गोताखोरों ने बचा लिया। किशोर अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए मुरादनगर आया था। सिकंदराबाद के रहने वाले राजकुमार का एक 17 वर्षीय पुत्र सुमित है। सुमित शुक्रवार रात को अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए मुरादनगर स्थित गंगनहर घाट पर आया था। रात को करीब नौ बजे गहरे पानी में जाने के कारण किशोर व उसका दोस्त डूबने लगे। दोनों की आवाज सुनकर गोताखोरों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। गोताखोरों ने साथी को तो बचा लिया, लेकिन सुमित पानी में डूब गया। करीब एक घंटे के अभियान के बाद गोताखोरों ने सुमित के शव को बरामद करा लिया। हादसे की खबर मिलने के बाद किशोर के घर में शोक व्याप्त हो गया। एसीपी का कहना है कि हादसों को देखते हुए घाट पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पत्रकारिता और राजनीति की दिशाहीनता का यक्ष प्रश्न

कमलेश पांडे

आम चुनाव 2024 के बाद यह सवाल सदैव मौजूं रहेगा कि आज 'बहुमत' के घमचक्कर में राजनीति और 'विज्ञापन' के चक्कर में पत्रकारिता जो अपने स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों से भटक चुकी है, उन्हें कैसे फिर से पटरी पर लाया जाए।

आम चुनाव 2024 के सातवें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है और मतगणना 4 जून को होगी। शुरुआती रूझान शनिवार एक जून की शाम में और अंतिम परिणाम मंगलवार चार जून की रात तक मिल जाएंगे। अब इसका परिणाम चाहे जो भी आए, लेकिन ये परिणाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और इंडिया गठबंधन की निकट भविष्य की चुनौतियों को बढ़ाने वाले साबित होंगे। ये चुनाव परिणाम पत्रकारिता और राजनीति की दिशाहीनता को भी उजागर करेंगे, जिससे निकट भविष्य की नई सियासी दिशा भी तय होगी।

ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस को साधकर या फिर कहीं कहीं खुद अपने दम पर भी क्षेत्रीय दलों ने आशातीत सियासी मजबूती हासिल कर ली है। इसलिए उनके क्षेत्रीय आकांक्षाओं और सियासी स्वार्थ को पूरे करने में भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों की घिग्गी बंध जाएगी। इस चुनाव में जो मुद्दे उठे, उससे भी इसी बात के संकेत मिलते हैं।

आम चुनाव 2024 के बाद यह सवाल सदैव मौजूं रहेगा कि आज 'बहुमत' के घमचक्कर में राजनीति और 'विज्ञापन' के चक्कर में पत्रकारिता जो अपने स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों से भटक चुकी है, उन्हें कैसे फिर से पटरी पर लाया जाए। क्योंकि जिन बेसिर-पैर के मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया, उसका प्रत्यक्ष व परोक्ष असर कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ-साथ समाजपालिका (सिविल सोसाइटीज) पर भी पड़ेगा।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि जनसंतुष्टिकरण के नाम पर तमाम सियासी उलटबांसी परोसने के बावजूद भी जब मतदाताओं ने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोर राष्ट्रवादी मुद्दों पर एक बार फिर से लौटने को विवश हुई। वहीं, कांग्रेस पार्टी भी अपनी विवादास्पद तुष्टिकरण की नीति के साथ-साथ जनसामान्य से जुड़े मुद्दों पर सर्वाधिक मुखर नजर आई। वहीं, भाजपा और कांग्रेस के समर्थक दल अपने जातीय, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर सर्वाधिक कसरत करते नजर आए।

इसका राजनीतिक दुष्परिणाम यह हुआ कि भाजपा भले ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आए, लेकिन उसके नेतृत्व वाला गठबंधन भी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से दूर ही रहेगा। उधर कांग्रेस के साथ साथ उसके साथी दलों के बेहतर सियासी प्रदर्शन की उम्मीद के बावजूद भी इस बात के पक्के आसार हैं कि वह भी बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर ही रहेगी। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, और बसपा आदि के सियासी पैंतरे यह तय करेंगे कि केंद्र में अगली सरकार किसकी बनेगी और कितने दिन तक चलेगी।

अब बात करते हैं उन चुनावी मुद्दों की जो उत्तर में राम-मंदिर से शुरू होकर दक्षिण में ध्यान-मुद्रा तक जाकर समाप्त हुए।हालांकि, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा जैसा सियासी शगूफा सब पर भारी पड़ा। क्योंकि इस मुद्दे ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक को एक बार फिर से उसके साथ जोड़ दिया। इससे उसके गठबंधन साथी भी लाभान्वित हुए। जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक और जातीय जनगणना, मतदाताओं के बीच मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर स्थानीय मुद्दों के भारी पड़ने आदि की बात है सो अलग। मीट और मुजरा आदि की बात करना तो बौद्धिक दिवालियापन का द्योतक होगा!

यदि निष्पक्षता पूर्वक कहा जाए तो एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और बसपा-बीजद-टीएमसी जैसे गठबंधन रहित दल ने आम चुनाव 2024 में ऐसे-ऐसे आधारहीन और भावनात्मक मुद्दे उठाए, जो समाज को जागरूक बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के सियासी पैमाने पर कहीं नहीं टिकते। वहीं, अपनी बातों-जज्बातों से अक्सर इन्हें जगाते रहने वाली मीडिया भी इस बार बिल्कुल असहाय नजर आई, क्योंकि सोशल मीडिया से उपजा जनज्वार उनको विभिन्न मोर्चों पर अप्रासंगिक बना दिया।

इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब जनता भी राजनेताओं की तरह ही पत्रकारों की कथनी और करनी से वाकिफ हो चुकी है। इसलिए वह भी अब इन्हें गम्भीरता से नहीं लेती और सोशल मीडिया मंचों पर अपनी बात रखते हुए वहीं से रूझानों की फीडबैक भी लेती है। इससे जहां यूट्यूब चैनल और वेब मीडिया की मांग बढ़ी है, वहीं टीवी चैनल्स और अखबार अपने वजूद के लिए संघर्षरत हैं!

ऐसा इसलिए कि भले ही पत्रकारिता और राजनीति में चोली-दामन का रिश्ता बताया जाता है। लेकिन इनके बीच भी पारस्परिक विश्वसनीयता घटी है। जब से दलगत सांचे में भारतीय पत्रकारिता ढली है, तब से मुख्य धारा की पत्रकारिता बदनाम हुई है। इससे उनकी सहायक धाराएं भी अछूती नहीं बचीं हैं। इसलिए कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि जनहित की समग्र दृष्टि से आज राजनीति और पत्रकारिता दोनों पेशा दिशाहीन हो चुका है। समाज को जागरूक और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का जो काम इन्हें करना चाहिए, वो आज निष्पक्षता पूर्वक नहीं हो पा रहा है।

बानगी स्वरूप यह बताया जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के ₹अबकी बार, 400 पार₹ के नारे को तमाम मीडिया प्रोपगेंडा के बावजूद आम चुनाव के प्रथम चरण से अंतिम सातवें चरण तक कायम नहीं रखा जा सका। वहीं, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का नारा बिना किसी संगठित प्रयास के ही पहले चरण से अंतिम चरण तक अपना गम्भीर असर दिखाता रहा। जबकि मौखिक प्रचार और सोशल मीडिया के अलावा कहीं पर भी टीवी या अखबार में इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई।

यह स्थिति समसामयिक राजनीतिक चिंतन और मीडिया विमर्श के लिए एक अहम कड़ी है, जिसकी उपयोगिता को समझने और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। चाहे सियासी मुफ्तखोरी पर न्यायिक स्टैंड का सवाल हो, या लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के नाम पर विदेशी ताकतों के हाथों खेलने की सियासी भूल हो, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से सियासी आंखमिचौली हो या फिर अग्निवीर और जनहित वाली गारंटियों का सवाल, जवाब मिलने में कुछ वक्त तो लगेगा ही।

अब देखना यह है कि राजनीति और पत्रकारिता की दिशाहीनता के बीच इन बातों-जज्बातों से भारत का हित सधेगा या फिर पीएम मोदी विरोधी चीनी-अमेरिकी चाल सफल होगी, इसका जवाब तो बदलता वक्त देगा, हम और आप तो संघर्षरत भारत और भारतीयता के बीच केवल मुक़द्रष्टा होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं!

वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार

टोयोटा फॉर्च्यूनर को कड़ी चुनौती देने इस तारीख को आ रही है एमजी ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट, जानें क्या होंगे बदलाव

ब्रिटिश वाहन निर्माता एमजी मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक से लेकर फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में कई वाहनों को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से जल्द ही Toyota Fortuner को और बेहतर तरीके से चुनौती देने के लिए Gloster के Facelift वर्जन को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इसे किन बदलावों के साथ कब लॉन्च करेगी। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कई बेहतरीन कारों और एसयूवी की बिक्री करने वाली ब्रिटिश वाहन निर्माता MG Motors की ओर से जल्द ही फुल साइज एसयूवी Gloster के Facelift वर्जन को लॉन्च करने वाली है। इसमें किस तरह के बदलाव किए जाएंगे और इसे कब लॉन्च किया जा रहा है। आइए जानते हैं।

June में लॉन्च होगी MG Gloster Facelift

एमजी मोटर्स की ओर से फुल साइज एसयूवी के तौर पर पेश की जाने वाली Gloster का Facelift वर्जन June 2024 में लॉन्च की जाएगी। कंपनी की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है कि इसे पांच जून को लॉन्च किया जाएगा।

लॉन्च से पहले जारी हुआ टीजर

कंपनी की ओर से MG Gloster Facelift के लॉन्च से पहले सोशल मीडिया पर 15 सेकेंड का एक टीजर जारी किया गया है। इस टीजर में Gloster के Facelift वर्जन की झलक दिखाई गई है। टीजर में एक कांच की बोतल में ऊपर से रेत गिरता हुआ दिखाया गया है। जिसमें Gloster Facelift की झलक दिखाई गई है। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि तीन दिन बाद नई एमजी ग्लॉस्टर को लाया जाएगा।

क्या होंगे बदलाव

कंपनी की ओर से अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन, फेसलिफ्ट वर्जन में कंपनी एसयूवी के एक्सटीरियर में बंपर, ग्रिल, हैडलैंप, टेल लैंप और अलॉय व्हील्स में बदलाव कर सकती है। इंटीरियर में भी इस एसयूवी में कई बदलावों के साथ कुछ नए फीचर्स को दिया जा सकता है। लेकिन इंजन और ट्रांसमिशन में किसी तरह का बदलाव होने की संभावना कम है। एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन में कुछ नए रंगों को भी ऑफर किया जा सकता है, जिसमें Dester Storm पेंट स्कीम को भी शामिल किया जा सकता है।

टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

ब्रिटिश कार निर्माता एमजी की ओर से भारतीय बाजार में फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में ग्लॉस्टर को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस एसयूवी को सात सीटों के विकल्प के साथ लाया जाता है। लॉन्च से पहले इस एसयूवी को कई बार सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है।

जून 2024 में होंडा समर बोनान्ज़ा हुआ शुरू, हजारों रुपये के गिफ्ट के साथ मिल रहा पेरिस घूमने का मौका

भारत की प्रमुख कार और एसयूवी ऑफर करने वाली जापानी कंपनी Honda Cars की ओर से June 2024 में Honda Summer Bonanza की शुरूआत की गई है। जिसमें कंपनी की ओर से विजेता को Paris घूमने का मौका भी दिया जा रहा है। यह स्कीम कब तक मान्य रहेगी और क्या फायदे कंपनी की ओर से दिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। अगर आप June 2024 में नई कार या एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो Honda Cars की ओर से अपनी कारों और एसयूवी पर हजारों रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी ने Honda Summer Bonanza शुरू किया है। कंपनी की ओर से किस कार और एसयूवी पर कितना डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Honda Summer Bonanza की हुई शुरूआत

जापानी वाहन निर्माता होंडा की ओर से Honda Summer Bonanza की शुरूआत की गई है। कंपनी की ओर से बताया है कि इस दौरान कोई भी ग्राहक होंडा की अमेज, एलीवेट या सिटी में से किसी भी कार को खरीदता है तो उसे इस स्कीम के तहत बड़े फायदे मिल सकते हैं। इस स्कीम के तहत देशभर में ग्राहक एक जून से लेकर 30 जून 2024 तक फायदा उठा सकते हैं।

मिलेंगे ये फायदे

कंपनी ने बताया है कि होंडा समर बोनान्जा के तहत ग्राहकों को Paris का कपल ट्रिप भी मिल सकता है। इसके साथ ही 75 हजार रुपये तक की कीमत के निश्चित गिफ्ट्स को दिया जा रहा है। कंपनी सिर्फ कार खरीदने वाले ग्राहकों को ही तोहफा नहीं दे रही है, बल्कि अगर कोई व्यक्ति इस महीने में किसी भी कार की टेस्ट ड्राइव करता है, तो उसे सरप्राइज के तौर पर गिफ्ट दिया जाएगा।

कंपनी के अधिकारियों ने कही यह बात

होंडा कार्स इंडिया के मार्केटिंग और सेल्स उपाध्यक्ष कुणाल बहल ने कहा किहम इस गर्मी में होंडा कार्स इंडिया होंडा कारों की खरीद पर विशेष लाभ प्रदान करते हुए 'होंडा समर बोनान्ज़ा' लाने के लिए रोमांचित है। इस अभियान के माध्यम से, हम चाहते हैं कि हमारे ग्राहक अपने पसंदीदा होंडा वाहन को घर ले जाएं। इस दौरान ग्राहकों को न केवल असाधारण मूल्य मिलेगा बल्कि इन रोमांचक ऑफ़र का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। हम अपने सभी ग्राहकों को इन आकर्षक लाभों का लाभ उठाने और अपने नज़दीकी डीलरशिप पर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।₹

कैसा है पोर्टफोलियो

कंपनी की ओर से भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट साइज सेडान के तौर पर अमेज को ऑफर किया जाता है। इसकी एक्स शोरूम कीमत की शुरूआत 7.93 लाख रुपये से हो जाती है। इसके अलावा कंपनी मिड साइज सेडान के तौर पर सिटी और सिटी e:HEV को ऑफर करती है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 12.08 लाख रुपये और 20.55 लाख रुपये से शुरू होती है। होंडा मिड साइज एसयूवी के तौर पर एलीवेट को ऑफर करती है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 11.91 लाख रुपये से शुरू हो जाती है।

सुज़ुकी और हीरो मोटोकॉर्प ने मई 2024 में कैसा किया प्रदर्शन, जानें किसने बेचे कितने वाहन

भारतीय बाजार में हर साल लाखों की संख्या में दो पहिया वाहनों की बिक्री होती है। इस सेगमेंट में कई कंपनियों की ओर से कई कुछ बेहतरीन वाहनों को ऑफर किया जाता है। बीते महीने में Hero Motocorp और Suzuki ने कितने वाहनों की बिक्री की है। May 2024 दोनों कंपनियों के लिए कितना बेहतर रहा है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में हर महीने बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री होती है। इनमें सबसे ज्यादा बिक्री दो पहिया वाहन सेगमेंट में होती है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि May 2024 में Hero Motocorp और Suzuki Motorcycle ने कितने यूनिट्स वाहनों की बिक्री की है।

Hero Motocorp के लिए कैसा रहा May 2024

भारत की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माताओं में शामिल Hero Motocorp ने May 2024 में 4.98 लाख यूनिट्स वाहनों की बिक्री की है। कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक बीते महीने में कुल 471186 यूनिट्स बाइक्स और 26937 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री हुई है। वहीं पिछले साल कंपनी ने कुल 5.19 लाख यूनिट्स वाहनों की बिक्री की थी। जिसमें 489336 यूनिट बाइक्स और 30138 यूनिट्स स्कूटर शामिल थे। कंपनी ने घरेलू बाजार में बीते महीने कम वाहनों बिक्री की है लेकिन निर्यात के मामले में कंपनी को ग्रोथ हासिल हुई है। May 2024 में भारत में कंपनी ने 479450 यूनिट्स की बिक्री की है। May 2023 में घरेलू बाजार में कंपनी ने 508309 यूनिट्स की बिक्री की थी। हीरो मोटोकॉर्प ने May 2024 में 18673 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया है। जबकि May 2023 के दौरान यह संख्या 11165 यूनिट्स की थी।

Suzuki को May 2024 में हासिल हुई बढ़त

जापानी दो पहिया वाहन निर्माता Suzuki को भी May 2024 में बिक्री के मामले में बढ़त मिली है। कंपनी ने बीते महीने में कुल 111512 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की है। May 2023 में कंपनी ने कुल 91316 यूनिट्स की बिक्री की थी। ऐसे में आंकड़ों के मुताबिक कंपनी को बीते महीने में 22 फीसदी की ग्रोथ मिली है। भारतीय बाजार में कंपनी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है और करीब 37 फीसदी की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हासिल की है। कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक May 2023 में सुजुकी ने 67040 यूनिट्स की बिक्री घरेलू बाजार में की थी, लेकिन बीते महीने में कंपनी ने 92032 यूनिट्स की बिक्री की है। लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी को नेगेटिव ग्रोथ मिली है। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने कंपनी ने सिर्फ 19480 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया है, जबकि May 2023 के दौरान कंपनी ने 24276 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया था।

लॉन्च से पहले लीक हुआ टाटा अल्ट्रोज रेसर का ब्रॉशर, जानें कैसे होंगे फीचर्स और कितना दमदार होगा इंजन

Tata Motors की ओर से कई बेहतरीन एसयूवी और कारों को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से जल्द ही नई कार के तौर पर Tata Altroz Racer को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन लॉन्च से पहले ही इस प्रीमियम हैचबैक का ब्रॉशर लीक हो गया है। टाटा की इस कार में किस तरह के फीचर्स को दिया गया है और कितना दमदार इंजन इसमें मिलेगा। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख कार निर्माता Tata Motors की ओर से जल्द ही प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में Altroz Racer को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले इसका ब्रॉशर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। लीक हुए ब्रॉशर के मुताबिक इसके कितने वेरिएंट होंगे, इसमें किस तरह के फीचर्स मिलेंगे और कितना दमदार इंजन अल्ट्रोज रेसर में दिया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लीक हुआ Brochure

Tata Altroz Racer के लॉन्च से पहले इसका ब्रॉशर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। लीक हुई ब्रॉशर में इस प्रीमियम हैचबैक के कितने वेरिएंट्स लाए जाएंगे। इनमें किस तरह के फीचर्स को दिया जा रहा है और इसमें कितना दमदार इंजन दिया गया है। इसकी जानकारी सामने आ गई है।

कितने होंगे वेरिएंट

लीक हुई जानकारी के मुताबिक टाटा अल्ट्रोज रेसर को कुल तीन वेरिएंट में लाया जाएगा। जिसमें R1, R2 और R3 शामिल हैं। इसके बेस वेरिएंट के तौर पर R1 को ऑफर किया जाएगा जबकि मिड वेरिएंट के तौर पर R2 और टॉप वेरिएंट के तौर पर R3 को लाया जाएगा।

कैसे होंगे फीचर्स

कंपनी की ओर से इस कार में 16 इंच के अलॉय व्हील्स, लैदरेट सीट्स, 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, सात इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और एपल कार प्ले, एलईडी डीआरएल, रियर वाइपर और वॉशर, चार स्पीकर और चार ट्वविटर, प्रोजेक्टर हेडलैंप, फ्रंट फॉग लैंप, रियर डिफॉगर, फ्रंट आर्मरेस्ट, पावर विंडो, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट, रेन सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, एक्सप्रेस कूल, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, एयर प्यूरीफायर और छह एयरबैग जैसे फीचर्स दिए जाएंगे।

कितना दमदार होगा इंजन

कंपनी की ओर से अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लीक हुए ब्रॉशर के मुताबिक इसमें 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन दिया जाएगा जिसके साथ छह स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। इस इंजन से कार को 118 बीएचपी की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा।

कब होगी लॉन्च

कंपनी की ओर से अभी इस बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे सात जून 2024 के आस-पास लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च के समय इसकी संभावित एक्स शोरूम कीमत 10 से 13 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

इलेक्ट्रिक वाहन और लग्जरी कारों के भविष्य पर Audi इंडिया के हेड ने दैनिक जागरण से कही यह बड़ी बात, जानें पूरी डिटेल

जर्मनी की लग्जरी वाहन निर्माता Audi की ओर से कई बेहतरीन कारों और एसयूवी को भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन लग्जरी कारों के भविष्य और सेकेंड हैंड बाजार के साथ ही और किन किन मुद्दों पर जानकारी Audi इंडिया हेड ने दैनिक जागरण से खास बातचीत में दी है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कई कंपनियों की ओर से अपनी कारों, एमपीवी और एसयूवी सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। जिनमें कुछ कंपनियां लग्जरी कारों को भी ऑफर करती हैं। जिनमें जर्मनी की लग्जरी वाहन निर्माता Audi भी शामिल है। Audi इंडिया हेड बलबीर सिंह ढिल्लो ने दैनिक जागरण से बातचीत में किस तरह की जानकारी को साझा किया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

ऑडी इंडिया की कैसी रही बिक्री

ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लो ने बताया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 33 फीसदी की ग्रोथ हासिल की है। इस दौरान ऑडी इंडिया ने बाजार में कुल 7027 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की है। खास बात यह है कि कंपनी को 58 फीसदी बिक्री ऐसे ग्राहकों से होती है, जिनकी उम्र 50 साल से कम है। उन्होंने कहा कि कस्टमर लॉयल्टी आज के समय में काफी महत्वपूर्ण है और हमारी हर चौथी कार मौजूदा ग्राहक खरीदना पसंद करता है।

लग जरी सेगमेंट में होगी बढ़ोतरी

ऑडी इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लो ने कहा कि भारत में अभी भी लग्जरी कार बाजार अन्य बाजारों के मुकाबले काफी छोटा है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की काफी ज्यादा संभावना है। उनके मुताबिक लग्जरी कार बाजार में इलेक्ट्रिक लग्जरी वाहनों के लिए भी काफी ज्यादा संभावना है क्योंकि केंद्र और राज्यों की सरकारें इस सेगमेंट को काफी आकर्षक बना रही हैं। इसके साथ ही हमें इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स में लॉन्ग टर्म रोडमैप की भी जरूरत होगी जिससे बाजार को और बेहतर बनाया जा सके।

इलेक्ट्रिक सेगमेंट पर है फोकस

भारतीय बाजार में ऑडी की ओर से फिलहाल चार इलेक्ट्रिक लग्जरी कारों को ऑफर किया जाता है, जिनमें Q8 E-Tron और Q8 Sports back e-Tron जैसी कारें हैं। कंपनी जल्द ही बाजार में Q6 e-Tron को भी लाने जा रही है, जिसे कुछ समय पहले ही ग्लोबल बाजार में पेश किया गया है। फिलहाल कंपनी की कुल बिक्री का तीन फीसदी हिस्सा ही इलेक्ट्रिक कारों से आता है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि साल 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 50 फीसदी तक हो जाएगा। Audi India की कोशिश है कि जल्द से जल्द भारत में ही इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोडक्शन किया जाए, इसके लिए कंपनी ग्लोबल हेडर्क्वाटर से लगातार संपर्क में है।

यूज्ड लग्जरी बाजार में भी बढ़ रही मांग

ऑडी इंडिया हेड बलबीर सिंह के मुताबिक भारत में नई लग्जरी कारों के साथ ही यूज्ड लग्जरी बाजार में भी लगातार मांग बढ़ रही है। कंपनी को जनवरी से मार्च 2024 के बीच इस सेगमेंट में 25 फीसदी की ग्रोथ हासिल हुई है। जिसे बढ़ाने पर कंपनी लगातार योजनाएं बना रही है। फिलहाल देशभर में कंपनी के 27 आऊटलेट हैं जहां पर यूज्ड लग्जरी कारों की बिक्री की जाती है और इनमें 300 से ज्यादा लग्जरी कारें ऑफर की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर हंगामा क्यों?

अवधेश कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी के विवेकानंद शिला स्मारक में ध्यान करना जितने बड़े विवाद और बवंडर का विषय बना उसे बिल्कुल स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। भारत सहित विश्व समुदाय को प्रेरणा देने वाले विवेकानंद के ध्यान स्थल से जुड़े इस केंद्र पर...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी के विवेकानंद शिला स्मारक में ध्यान करना जितने बड़े विवाद और बवंडर का विषय बना उसे बिल्कुल स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। भारत सहित विश्व समुदाय को प्रेरणा देने वाले विवेकानंद के ध्यान स्थल से जुड़े इस केंद्र पर प्रधानमंत्री जाकर ध्यान करते हैं तो इसका संदेश सर्वत्र जाता है और लोगों में भी विवेकानंद के जैसा बनने, विपरीत परिस्थिति में ध्यान करने और स्वयं को नियंत्रित कर देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। हालांकि हमारी राजनीति जहां पहुंच गई है वहां ऐसे विषयों का विरोध होना स्वाभाविक है।

प्रधानमंत्री ने विवेकानंद शिला स्मारक के जिस ध्यान मंडपम में ध्यान किया, ठीक उसी जगह पर 25, 26 ,27 दिसंबर, 1892 को स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान साधना किया था। माना जाता है कि वहां से उन्हें विशेष अनुभूति हुई और भारत के भविष्य की कल्पना भी जगी थी जो बाद के उनके भाषणों में संकलित है। विपक्ष ने यद्यपि बुद्धिमत्तापूर्वक कहा कि वे ध्यान साधना का विरोध नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से भाजपा को चुनावी लाभ हो जाएगा। मुद्दा यह बना दिया जाएगा कि देखो ये ध्यान साधना यानी सनातन की पद्धतियों के ही विरोधी हैं। इसलिए इसके टी.वी. कवरेज पर आपत्ति व्यक्त की गई। अलग-अलग पार्टियां चुनाव आयोग के पास गईं भी। प्रधानमंत्री या कोई नेता चुनाव प्रचार के बाद या बीच में किसी धर्मस्थल या प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल पर जाए, वहां पूजा, प्रार्थना, ध्यान या अन्य साधना करे उस पर चुनाव आयोग या कोई भी संवैधानिक संस्था कैसे रोक लगा सकती है?

विपक्ष के नेताओं ने भी पूरे चुनाव में परिश्रम किया है और उन्हें भी ध्यान साधना और शारीरिक, मानसिक संतुलन व शांति के लिए पहले से ऐसी कुछ योजना बनानी चाहिए थी। भारत में अनेक ऐसे धार्मिक साधना स्थल हैं जहां जाकर आप शारीरिक- मानसिक थकान से आध्यात्मिक कृतियों के द्वारा मुक्ति पा सकते हैं। ऐसी जगह भी है जहां जाकर 1-2 दिनों के विश्राम से आपको विशेष शांति और शक्ति मिलती है। अगर विपक्ष के नेताओं में ऐसी दृष्टि नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रधानमंत्री या कोई भी सत्तारुढ़ पार्टी का नेता उस दिशा में न सोचे न करे। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सभी चाहें तो कहीं न कहीं ऐसी साधना कर सकते थे और उन्हें भी टैलीविजन या मीडिया का कवरेज मिलता।

नेताओं में वाकई ध्यान और साधना की प्रतिस्पर्धा हो तो यह देश और संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी होगा। जब आध्यात्मिक दृष्टि से आपके शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित होता है तो उसके साथ सकारात्मक दृष्टि भी विकसित होती है जहां से केवल सबके कल्याण के भाव से ही विचार पैदा हो सकते हैं। विपक्ष के नेता ऐसा कार्यक्रम करने की बजाय अगर विरोध कर रहे हैं तो वे देश में नकारात्मक वातावरण बनाते हैं और उनकी अपनी छवि ही कमजोर होती है। जब 2014 का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने शिवाजी के रायगढ़ किले में जाकर ध्यान किया था। शिवाजी हमारे देश में भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व की दृष्टि से प्रेरक और आदर्श व्यक्तित्व हैं। शिवाजी जैसे महापुरुष के प्रति अगर विपक्ष के अंदर ऐसा भाव पैदा नहीं होता तो इसके लिए वही दोषी हैं।

2019 के चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड के केदारनाथ गए थे और वहां उन्होंने गुफा में ध्यान और साधना की। प्रधानमंत्री के जाने के बाद से उस गुफा में ध्यान करने वालों की इतनी संख्या बढ़ी कि लंबे इंतजार के बाद नंबर आता है। विपक्ष के किसी नेता को किसी भी पूजा स्थल, आध्यात्मिक स्थल, प्रेरणा के केंद्र, इबादत स्थल या कहीं जाकर ऐसा कुछ करने से किसी ने रोका नहीं है। उनको इसकी समझ नहीं या राजनीति से परे हटकर वे आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ करने का विचार नहीं कर सकते तो यह उनकी समस्या है। यह मान लेना कि इस प्रकार की ध्यान साधना या पूजा-पाठ के मीडिया कवरेज के प्रभाव में आकर पहले से किसी और को मत देने का मन बनाए मतदाता अचानक पलट कर भाजपा को वोट देने लगेंगे उचित नहीं लगता। मतदाताओं के पास भी सही गलत का निर्णय करने का विवेक है।

अगर विपक्ष इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति मानता है तो उसे भी इसकी काट में रणनीति अपनानी चाहिए। इसके विपरीत जब ये हंगामा

करते हैं, चुनाव आयोग जाते हैं तो भाजपा के समर्थकों के साथ-साथ हिंदुत्व को लेकर संवेदनशील रहने वाले मतदाताओं को लगता है कि वाकई विपक्ष सनातन और हिंदुत्व विरोधी है। इसलिए इस व्यवहार को रणनीतिक भूल मानने में भी हर्ज नहीं है। विरोधियों ने प्रधानमंत्री की ध्यान साधना को राजनीतिक मुद्दा बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया। अगर इतना तीखा और आक्रामक विरोध नहीं होता तो मुख्य मीडिया और सोशल मीडिया से लेकर जनता के बीच इसकी इतनी चर्चा ही नहीं होती। किसी भी देश का शीर्ष नेता चाहे प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति ध्यान साधना या अपने आध्यात्मिक कर्मकांड या फिर छुट्टियां मनाने जाएगा तो उसे मीडिया का कवरेज मिलेगा।

प्रधानमंत्री जब तक वहां रहे तब तक भारत ही नहीं दुनिया भर के भारत में सक्रिय मीडिया और पत्रकारों का जमावड़ा वहां रहा। इसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन इनकी समस्या दूसरी है। नेताओं के मन में यह ग्रंथि है कि ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा मुस्लिम वोट खिसक सकता है। लंबे समय से नेताओं के द्वारा इस तरह की भूमिका को सैक्युलर विरोधी या पिछड़ेपन की दृष्टि से देखा गया और समाज का मनोविज्ञान इसी अनुसार निर्मित हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो एक बहुत बड़े वर्ग को वह सहज और स्वाभाविक भी नहीं लगता। विवेकानंद शिला स्मारक पर जाने वाले या उसकी प्रशंसा करने वाले ज्यादातर नेताओं को शायद यह पता नहीं होगा कि उसके निर्माण के पीछे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्य भूमिका थी।

1963 में स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी के समय लोगों ने उस चट्टान के पास एक स्मारक बनाने का निश्चय किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। संघ ने अपने उस समय के वरिष्ठ प्रचारक एकनाथ रानाडे को इस काम में लगाया। उन्होंने इसके लिए लोगों को जोड़ा, बैठकें कीं, सभाएं कीं, सरकारों से संपर्क किया, चंदे एकत्र किए और फिर उसका अत्यंत कठिनाई से निर्माण हुआ। उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम् ने स्मारक में मदद से मना कर दिया। तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्री हुमायूं कबीर ने भी सहयोग से इंकार किया। संघ ने निर्णय कर लिया था और उनके लोग लग गए थे तो वे लगे रहे। सांसदों से भेंट की गई। 300 से ज्यादा सांसदों से हस्ताक्षरित समर्थन लिया गया। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उसके निर्माण की अनुमति दी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए 1 रुपया से 5 रुपया का चंदा लिया गया तथा माहौल बनने के बाद राज्य सरकारों ने भी एक लाख का योगदान दिया। 1972 में विवेकानंद केंद्र बना जो वहां अनेक प्रकार के कार्यक्रम करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस तरह की आलोचना केवल लंबे समय से पाले गए और स्वाभाविक दुराग्रह की परिणति होती है। वहीं से ऐसे विरोध पैदा होते हैं जिनका आम जनता पर असर न के बराबर होता है।

संपादक की कलम से

अब सट्टा बाजार और एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में

भारी हीट वेव के बीच देश में लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर हिंसा, तोड़-फोड़ और वोटिंग मशीनों में खराबी के चलते लोगों की नाराजगी के बीच पूरी हो गई। इन चुनावों के दौरान किसी भी चरण में वर्ष 2019 के चुनावों के आंकड़े के बराबर मतदान नहीं हुआ जिसका कारण प्रचंड गर्मी के मौसम में चुनाव करवाना ही है। लोगों का कहना है कि जब मौसम विभाग ने काफी पहले ही इस वर्ष अधिक गर्मी पडने की चेतावनी दे रखी थी तो चुनाव तिथियों का निर्धारण कुछ आगे-पीछे किया जा सकता था।

ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने मतदान में 'नोटा' का बटन तो नहीं दबाया लेकिन इसलिए मतदान करने नहीं गए कि उनका मानना था कि सभी उम्मीदवार एक जैसे ही हैं जिनसे उन्हें अपनी समस्याएं सुलझने की कोई उम्मीद नहीं। जब लगातार बिजली व पानी जैसी सुविधाएं ही नहीं मिल रहीं तो हम वोट डालने क्यों जाएं? कमर तोड़ महंगाई भी लोगों की मतदान से दूरी का कारण बनी। इन चुनावों में गर्मी के कारण न सिर्फ मतदान करने आए लोगों बल्कि मतदान सम्पन्न करवाने वाले अधिकारियों को भी अपने प्राण गंवाने पड़े। 31 मई को ही बिहार में 14 और उत्तर प्रदेश में 18 मतदान अधिकारियों की मौत हो गई।

2019 में चुनाव आयोग ने 3475 करोड़ रुपए की नकद राशि और नशीली दवाएं जब्त की थीं, जबकि इस बार अब तक के 75 वर्ष के इतिहास में सर्वाधिक अवैध रकम तथा वस्तुएं जब्त की हैं। 18 मई, 2024 तक नशीले पदार्थों व नकदी आदि सहित कुल 8889 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुएं जब्त की गईं। पंजाब में 30 मई तक कुल 801.87 करोड़ रुपए की नकदी एवं वस्तुएं जब्त की गईं। इस बार पंजाब और चंडीगढ़ में उम्मीदवारों ने वोट खरीदने के लिए लोगों को 10, 20 और 100 मूल्य वाले नोट 'कूपनों' की तरह बांटे, जिन्हें निर्धारित दुकानदारों को पेश करके उन्होंने उनके बदले में तयशुदा वस्तुएं प्राप्त कीं।

जब कोई व्यक्ति उक्त नोट लेकर वैंडर के पास जाता तो वैंडर उस नोट के नम्बर का उम्मीदवार द्वारा दी गई नोटों की सूची के नम्बर से मिलान करके उन्हें उसके बदले में वस्तुएं (राशन, उपहार, शराब आदि) दे देता था। कई जगह उम्मीदवारों द्वारा वोट खरीदने के लिए पंखे व कूलर बांटने के भी समाचार हैं। सट्टा बाजार में भावी सरकार को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं व अधिकांश सट्टा बाजारों ने भाजपा के पक्ष में अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान में फालोदी के सट्टा बाजार ने भाजपा गठबंधन को 290-300 सीटें दी हैं। मुम्बई के सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा को अकेले 295 से 305 सीटें तथा कांग्रेस को 55 से 65 सीटें मिल सकती हैं।

पालनपुर सट्टा बाजार ने राजग को 247 (भाजपा 216), इंडिया को 225 (कांग्रेस 112), करनाल सट्टा बाजार ने राजग को 263 (भाजपा 235) और इंडिया को 231 (कांग्रेस 108), बेलगाम सट्टा बाजार ने राजग को 265 (भाजपा 223), इंडिया को 230 (कांग्रेस 120), इंदौर सर्राफा ने राजग को बहुमत तथा भाजपा को 260, इंडिया को 231 (कांग्रेस 108), कोलकाता सट्टा बाजार ने राजग को 261 (भाजपा 218), इंडिया को 228 (कांग्रेस 128), विजयवाड़ा सट्टा बाजार ने राजग को 252 (भाजपा 224) तथा इंडिया को 237 (कांग्रेस को 121) सीटें दी हैं। मतदान समाप्त होते ही एग्जिट पोल भी आ गए हैं जिनमें भाजपा नीत राजग गठबंधन का ही पलड़ा भारी बताया जा रहा है तथा इसे प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है।

रिपब्लिक टी.वी.-मैट्रीज ने भाजपा नीत राजग को 353 से 368, इंडिया को 118-133, रिपब्लिक टी.वी.-पी मार्क ने राजग को 359, इंडिया को 154, 'जन की बात' ने राजग को 362-392, इंडिया को 141-161, इंडिया टी.वी.-सी.एन.एक्स. ने राजग को 371-401 तथा इंडिया को 109-139 सीटें दी हैं।

चिंतन

अग्नि सुरक्षा के प्रति ढीला रवैया बदलना होगा

आग की खोज मानव इतिहास में महत्वपूर्ण थी, लेकिन आग भी बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकती है। आग ने महत्वपूर्ण मानवीय उपलब्धियों को बनाया भी है और नष्ट भी किया है। इसने पूरे शहरों, ऊंची संरचनाओं, मलिन बस्तियों, बाजारों और पूजा स्थलों को लगातार...

आग की खोज मानव इतिहास में महत्वपूर्ण थी, लेकिन आग भी बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकती है। आग ने महत्वपूर्ण मानवीय उपलब्धियों को बनाया भी है और नष्ट भी किया है। इसने पूरे शहरों, ऊंची संरचनाओं, मलिन बस्तियों, बाजारों और पूजा स्थलों को लगातार प्रभावित किया है। हालांकि, प्रत्येक आपदा को भविष्य की घटनाओं के लिए सीखने और तैयारियों में सुधार करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। उदाहरण के लिए, 1871 की ग्रेट शिकागो फायर ने सार्वजनिक सुरक्षा और आग की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसमें आग प्रतिरोधी सामग्री की आवश्यकता वाले सख्त बिल्डिंग कोड, बेहतर अग्निरोधक मानक, एक बेहतर अग्निशमन विभाग, बेहतर जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, शहरी आग की रोकथाम, सार्वजनिक सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना और आग पर सार्वजनिक शिक्षा में वृद्धि शामिल है।

भारत में आग लगने का एक पुराना इतिहास है, जिसमें अस्पताल में लगी आग भी शामिल है। 2021 में भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल की शिशु देखभाल इकाई में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 4 नवजात बच्चों की जान चली गई और अन्य घायल हो गए। 1984 की कुख्यात भोपाल गैस रिसाव आपदा भारत के अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल को संबोधित करने की तात्कालिकता को और बढ़ा देती है। हाल की घटनाओं में, देश 2 विनाशकारी अग्नि त्रासदियों से हिल गया। राजकोट में एक मनोरंजन पार्क में वैल्डिंग मशीन से निकली चिंगारी के कारण 33 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी घटना, पूर्वी दिल्ली में एक नवजात शिशु सुविधा केंद्र-'बेबी केयर न्यू बोर्न चाइल्ड हॉस्पिटल' में आग लगने से देश भर में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में घातक आग लगने की एक दुखद श्रृंखला जुड़ गई है, जो ढीली अग्नि सुरक्षा के घातक परिणामों को उजागर करती है। 8 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य को बचा लिया गया और दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

एफ.आई.आर. में बताया गया कि अस्पताल में 27 ऑक्सीजन सिलैंडर पाए गए, जिनमें से 5 आग के दौरान फट गए। अस्पताल में आपातकालीन निकास, कार्यात्मक अग्निशामक यंत्र और परिचालन अग्नि अलार्म जैसे उचित सुरक्षा उपायों का अभाव था। आग लगने के दौरान मौजूद नर्सों ने बताया कि कई बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अस्पताल के कर्मचारियों के बीच गंभीर सुरक्षा खामियों और अपर्याप्त आपातकालीन प्रशिक्षण का उल्लेख किया। स्थानीय निवासियों ने पहले अस्पताल के सुरक्षा खतरों, विशेष रूप से ऑक्सीजन सिलैंडरों के भंडारण और प्रबंधन के बारे में शिकायत की थी।

घटना के बाद, दिल्ली सरकार ने 8 जून तक सभी अस्पतालों के लिए अग्नि सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया और जांच की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री ने खुलासा किया कि अस्पताल में पहले से ही कमियां थीं और वह अवैध रूप से ऑक्सीजन सिलैंडर भर रहा था जिससे आग लगने की संभावना थी।

छोटे अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा लागू करने की दिल्ली सरकार की योजना, ज्यादा से ज्यादा, कागजों पर ही रह गई है। 5 साल पहले, दिल्ली सरकार ने छोटे अस्पतालों और नृसग होमों को अग्नि सुरक्षा नियमों के तहत लाने के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया था। हालांकि, इन दिशा-निर्देशों को कभी लागू नहीं किया गया, जिससे एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दा अनसुलझा रह गया। नागरिक देखभाल के एक महत्वपूर्ण पहलू के प्रति यह आधिकारिक उदासीनता चौंकाने वाली है। दुर्भाग्य से, अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों और क्लीनिकों पर नजर रखने में भी खामियां हैं। वास्तव में छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होमों के लिए अग्नि सुरक्षा नियम बहुत सख्त हैं जिसके कारण लगभग 600 ऐसी सुविधाओं में गैर-अनुपालन होता है।

गुड़गांव उन चिकित्सा सुविधाओं पर अपनी कार्रवाई तेज कर रहा है जिनमें पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी है। हालांकि, बिस्तरों की संख्या, भवन की ऊंचाई और क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग नियम लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, 2018 में हरियाणा सरकार का क्लिनिकल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट केवल 50 बिस्तरों से अधिक वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिससे छोटे अस्पताल इसके दायरे से बाहर हो जाते हैं। जैसे-जैसे अस्पताल में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि जीवन की और हानि को रोकने और मरीजों और चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए।

1997 की उपहार सिनेमा त्रासदी सबसे कुख्यात अग्नि आपदाओं में से एक है। यह स्पष्ट रूप से मालिकों और नागरिक अधिकारियों दोनों द्वारा कानून के उल्लंघन को दर्शाता है। मालिकों को लापरवाही और सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी ठहराया गया। हालांकि, अंसल बंधुओं को कम सजा देने की अनुमति देने के न्यायपालिका के फैसले की व्यापक रूप से निंदा की गई है। यह अत्यंत खेदजनक है। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) ने आग को मानव निर्मित आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है। राजकोट और नवजात अस्पताल में त्रासदियां मानव निर्मित थीं और पूरी तरह से टाली जा सकती थीं। जबकि अस्पताल के मालिक और एक ऑन-ड्यूटी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया, लेकिन अपूर्णीय क्षति पहले ही हो चुकी है।

दुर्भाग्य से हम तब तक लापरवाह बने रहते हैं जब तक कि आपदाएं नहीं आतीं, और केवल तात्कालिक खतरा टल जाने के बाद भूल जाते हैं। हमारे देश में बार-बार लगने वाली आग के लिए उदासीनता और अज्ञानता का बड़ा योगदान है। कई नागरिक सुरक्षा उपायों और नियमों की अनदेखी करते हैं, यहां तक कि निकास में बाधा डालते हैं और खतरनाक सामग्रियों का भंडारण करते हैं। अग्नि सुरक्षा के प्रति यह ढीला रवैया बदलना होगा। हमें सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए और आगे की पीड़ा को रोकने के लिए उनका उल्लंघन करने वालों को दंडित करना चाहिए।

जो साहस करता है वह जीतता है

मैंने पिछले सप्ताह के कॉलम को इन शब्दों के साथ समाप्त किया, ''जैसे ही चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ, लड़ाई यथास्थिति की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों और यथास्थिति को बाधित करने वाले लोगों के बीच शामिल हो गई।'' वोटों की गिनती में 2 दिन बाकी हैं और...

मैंने पिछले सप्ताह के कॉलम को इन शब्दों के साथ समाप्त किया, ''जैसे ही चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ, लड़ाई यथास्थिति की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों और यथास्थिति को बाधित करने वाले लोगों के बीच शामिल हो गई।'' वोटों की गिनती में 2 दिन बाकी हैं और हमें पता चल जाएगा कि बहुसंख्यक (या बहुसंख्यक) लोग बदलाव चाहते हैं या यथास्थिति बनाए रखने से खुश हैं।

यथास्थिति में आराम : निश्चित रूप से ऐसे बहुत से लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। मेरा मानना ऐसा इसलिए है क्योंकि परिवर्तन न करने वालों को यह डर रहता है कि परिवर्तन से उनका जीवन और भी बदतर हो सकता है या इसलिए कि अज्ञात ज्ञात से अधिक भयावह है या क्योंकि उन्हें डर है कि एक पहलू में बदलाव जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, परंपरा को तोडने से समुदाय के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। यथास्थिति में एक निश्चित आराम है। भारत के पिछले 30 वर्षों में कुछ ऐसे कालखंड रहे हैं जहां प्रेरक शक्ति परिवर्तन थी, कुछ अन्य कालखंडों के दौरान, यह यथास्थिति की रक्षा करना था। अन्य समय में, यह नास्तिकतावाद था, जिसे शब्दकोष 'उलटने की प्रवृत्ति' के रूप में परिभाषित करता है। (एटाविस्ट वे लोग हैं जो उस चीज की लालसा रखते हैं जिसे वे एक खोया हुआ और गौरवशाली अतीत मानते हैं।)

मेरा मानना है कि भारत को बदलाव की जरूरत है और वह बदलाव का हकदार भी है। 10 साल पहले बदलाव का शोर मचा और यू.पी.ए. से एन.डी.ए. में सत्ता परिवर्तन हुआ। मुझे लगता है कि भारत फिर से ऐसे ही क्षण में है। पिछले 10 वर्षों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसे बदला जाना चाहिए या सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। 2016 में नोटबंदी एक बड़ी गलती थी। तरलता में भारी छेद के कारण व्यक्तियों के जीवन के साथ-साथ सैंकड़ों-हजारों सूक्ष्म और लघु इकाइयों के कामकाज में भी उथल-पुथल मच गई। कई इकाइयां ठीक नहीं हुईं और बंद हो गईं।

कष्ट को सहने वाले : महामारी के वर्षों (2020 और 2021) के दौरान अनियोजित लॉकडाऊन ने स्थिति को और खराब कर दिया। वित्तीय पैकेज और ऋण के अभाव ने सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए स्थिति को और खराब कर दिया। अधिक इकाइयां बंद हो गईं और दोहरे झटके के परिणामस्वरूप, सैंकड़ों-हजारों नौकरियां चली गईं। गंभीर स्थिति को बदलने के लिए एक साहसिक योजना की आवश्यकता है जिसमें ऋण माफी, बड़े पैमाने पर ऋण, सरकारी खरीद, निर्यात प्रोत्साहन और कर रियायतें शामिल होंगी। मैंने नो-चेंजर्स (कोई परिवर्तक नहीं) से इस संबंध में किसी योजना के बारे में नहीं सुना है।

आरक्षण के मूक प्रहार ने एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के संवैधानिक वायदों को नष्ट कर दिया है। सरकारी और सरकारी क्षेत्र में 30 लाख नौकरियां खाली छोडना आपराधिक उपेक्षा और आरक्षण विरोधी रवैये का उदाहरण था। आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा की शपथ लेते हुए, यथास्थितिवादियों ने चुपचाप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए 50 प्रतिशत से ऊपर 10 प्रतिशत कोटा खिसका दिया, लेकिन एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के बीच ई.डब्ल्यू.एस. को बाहर कर दिया। क्यों? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नौकरियों की शुद्ध कटौती, आरक्षण पर शर्तों के बिना निजीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सरकार पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता, प्रश्नपत्रों के लीक का हवाला देकर सार्वजनिक परीक्षाओं को रद्द करना, गैर-सरकारी उद्यमों में नौकरियों की शुद्ध कमी से आरक्षण की नीति को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया गया है। पदोन्नति, और नौकरियों का संविदाकरण और अस्थायीकरण हुआ। परिवर्तन केवल उन लोगों के कहने पर आएगा जो यथास्थिति को चुनौती देते हैं।

नुकसान की भरपाई : कानूनों का हथियारीकरण उलटने योग्य है। एक संसद का प्रभुत्व कैसे होगा? पिछले 10 वर्षों में पारित किए गए कठोर नए विधेयकों या संशोधन विधेयकों को कोई परिवर्तनकत्ता उलट नहीं देगा? जांच एजैंसियों पर लगाम कौन लगाएगा और उन्हें संसद/विधान समितियों की निगरानी में कौन लाएगा? संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 22 के अर्थ और सामग्री को कौन पुनस्र्थापित करेगा और कानून का शासन फिर से स्थापित करेगा? 'बुल्डोजर न्याय' और 'प्री-ट्रायल कैद' को कौन समाप्त करेगा? लोगों में कानून का डर कौन दूर करेगा और उसकी जगह कानून के प्रति सम्मान कौन लाएगा? कौन 'उचित प्रक्रिया' को आपराधिक कानून का अपरिवर्तनीय सिद्धांत बनाएगा और कानून में इस सिद्धांत को शामिल करेगा कि 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है'? ये परिवर्तन केवल निडर कानून निर्माताओं द्वारा ही किए जा सकते हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

उदारीकरण, खुली अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धा और विश्व व्यापार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार लाया है लेकिन यह तभी प्रासंगिक रहेगा जब आर्थिक नीतियां दोबारा तय की जाएंगी। बढ़ते नियंत्रण, छिपी हुई लाइसैंसिंग, बढ़ते एकाधिकार, संरक्षणवाद और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के डर के कारण विकास दर में गिरावट आई है, जैसा कि होना ही था। श्रम की कीमत पर पूंजी के प्रति पूर्वाग्रह (हमारे पास पी.एल.आई. है लेकिन ई.एल.आई. नहीं) ने रोजगार और मजदूरी को दबा दिया है जो बढ़ती असमानता के कारणों में से एक है। विश्व असमानता लैब के अनुसार, भारत की असमानता 1922 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। औसत आय में वृद्धि से कई लोग धोखा खा जाते हैं। याद रखें, औसत से नीचे 50 प्रतिशत भारतीय लोग (71 करोड़) हैं और उसके भीतर नीचे के 20 प्रतिशत (28 करोड़) हैं जो और भी गरीब हैं। क्या यथास्थितिवादी निचले 20 प्रतिशत लोगों के लिए बोलेंगे?

एक अन्य डाटा बिंदु पर नजर डालें। भारत की वयस्क आबादी (15-64 वर्ष) 92 करोड़ है लेकिन केवल 60 करोड़ ही श्रम बल में हैं। श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.) का सबसे उदार अनुमान 74 प्रतिशत (पुरुष) और 49 प्रतिशत (महिला) है। असंतोषजनक एल.एफ.पी.आर., उच्च बेरोजगारी दर और बढ़ती आबादी को मिलाकर, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि हम तेजी से जनसांख्यिकी के फायदे खो रहे हैं। वर्तमान आर्थिक नीतियों को चुनौती देने और उन्हें नए सिरे से स्थापित करने का साहस कौन करेगा? यथास्थितिवादी नहीं। व्यवधान ही परिवर्तन लाएगा। व्यवधान और परिवर्तन, कई लाभ और कुछ नुकसान लाएंगे जिन्हें ठीक किया जा सकता है। 1991 का मुख्य सबक यह है कि जो साहस करता है वह जीतता है। यथास्थितिवादियों और नो चेंजर्स ने सबक नहीं सीखा है और न ही सीखेंगे।

एग्जिट पोल का शेयर मार्केट पर क्या होगा असर, किन बातों का ध्यान रखें निवेशक?

परिवहन विशेष न्यूज

एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि सत्तारूढ़ एनडीए तकरीबन 360 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे मई में बाजार पर पड़ने वाला तथाकथित चुनावी तनाव पूरी तरह से खत्म हो गया है। यह तेजड़ियों (Bulls) के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत है और वे सोमवार को बाजार में बड़ी तेजी लाएंगे।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई थी। उसके बाद से ही शेयर मार्केट में लगातार बिकवाली का रुख है। विदेशी निवेशकों ने भी चुनावी अनिश्चितता, खासकर शुरुआती चरण में कम वोटिंग के बाद जमकर निकासी की। हालांकि, अब एग्जिट पोल (Exit Poll) में सत्तारूढ़ बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए की मजबूत वापसी के संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगे।

आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि एग्जिट पोल का शेयर बाजार की चाल पर क्या असर पड़ेगा और इससे निवेशकों का रुख किस तरह से प्रभावित होगा। साथ ही, आने वाले हफ्ते में कौन से फैक्टर मार्केट में उतार-चढ़ाव की वजह बनेंगे।

क्या शेयर मार्केट में तेजी आएगी?

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटिजिस्ट वीके विजयकुमार मानना है कि एग्जिट पोल रिजल्ट (Exit polls results) से शेयर मार्केट में सोमवार को तेजी देखने को मिल सकती है। विजयकुमार ने कहा, 'एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि सत्तारूढ़ एनडीए तकरीबन 360 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है। इससे मई में बाजार पर पड़ने वाला तथाकथित चुनावी तनाव पूरी तरह से खत्म हो गया है। यह तेजड़ियों (Bulls) के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत है और वे सोमवार को बाजार में बड़ी तेजी लाएंगे।'

किन सेक्टर पर रहेगी नजर?

मौजूदा सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खास फोकस है। विजयकुमार का कहना है कि फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल और टेलिकॉम सेक्टर सोमवार को शेयर मार्केट में तेजी की अगुआई कर सकते हैं। वहीं, शुक्रवार को बाजार होने के बाद जीडीपी के आंकड़े भी आए, जो एक्सपर्ट के अनुमान से काफी बेहतर रहे। ऐसे में टेक्निकल और फंडामेंटली, दोनों तरीके से शेयर मार्केट रैली के लिए तैयार लग रहा है।

ये फैक्टर भी होंगे महत्वपूर्ण

जीडीपी डेटा और एग्जिट पोल के बाद अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम 4 जून (मंगलवार) होगा, जब लोकसभा चुनाव के नतीजों की आधिकारिक घोषणा होगी। इस सरकार को लेकर सारी अनिश्चितताएं दूर हो जाएंगी और उसी के हिसाब से शेयर मार्केट अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकती है। इसके बाद 7 जून को रिजर्व बैंक (RBI) अपनी मौद्रिक नीति का एलान करेगा। इसमें पता चलेगा कि रेट कट होगा या नहीं। इस पर निवेशकों को नजर रहेगी।

F&O ट्रेडिंग में बढ़ रहा रिटेल इन्वेस्टर का झुकाव; वित्त मंत्री, सेबी और एक्सपर्ट की बढ़ी चिंता

एक्सपर्ट का कहना है कि सट्टेबाजी स्वभाव वाले निवेश वायदा एवं विकल्प (FO) कारोबार के प्रति आकर्षित हो रहा हैं। सबसे चिंता की बात कि उन्हें इस सेगमेंट की जानकारी नहीं होती लेकिन जल्दी पैसा बनाने के लिए लालच में वे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और अपनी जमापूंजी गवां बैठते हैं। एक्सपर्ट की सलाह है कि खुदरा निवेशकों को पूरी जानकारी होने के बाद FO ट्रेडिंग करनी चाहिए।

नई दिल्ली। पिछले कुछ साल में शेयर बाजार ने काफी शानदार रिटर्न दिया है। इससे बहुत से नए और युवा निवेशकों का झुकाव भी इक्विटी मार्केट की तरफ हुआ है। लेकिन, बहुत से रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे भरोसेमंद तरीके के बजाय फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग जैसी जटिल और सट्टेबाजी समझी जाने वाली विधा में हाथ आजमा रहे हैं। इसमें उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।

क्या कह रहे एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट का कहना है कि सट्टेबाजी स्वभाव वाले निवेश वायदा एवं विकल्प (F&O) कारोबार के प्रति आकर्षित हो रहा हैं। सबसे चिंता की बात कि उन्हें इस सेगमेंट की जानकारी नहीं होती, लेकिन जल्दी पैसा बनाने के लिए लालच में वे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और अपनी जमापूंजी गवां बैठते हैं। एक्सपर्ट की सलाह है कि खुदरा निवेशकों को पूरी जानकारी होने के बाद F&O ट्रेडिंग करनी चाहिए।

वित्त मंत्री, सेबी भी चिंतित

पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने एफएंडओ ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टर की बढ़ती भागीदारी पर चिंता जाहिर की। पिछले साल नवंबर में सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच ने भी छोटे निवेशकों को आगाह किया था कि उन्हें एफएंडओ में ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए।

F&O से चिंता क्यों

दरअसल, एफएंडओ ट्रेडिंग की काफी जटिल विधा है। इससे रिटेल निवेशकों को सावधान करने का मकसद उन्हें किसी तरह के सट्टा कारोबार से दूर रखना है। हालांकि, भारी लाभ की संभावना के चलते खुदर निवेशक इसकी ओर खिचें चले जाते हैं।

कितना लोकप्रिय है F&O

F&O सेगमेंट की लोकप्रियता इसके बढ़ते कारोबार से स्पष्ट है। F&O सेगमेंट में मासिक कारोबार मार्च, 2024 में 8,740 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि मार्च 2019 में यह 217 लाख करोड़ रुपये था। वहीं, इक्विटी कैश सेगमेंट में औसत दैनिक कारोबार एक लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि एफएंडओ सेगमेंट में औसत दैनिक कारोबार लगभग 330 लाख करोड़ रहा है।

EPFO मेंबर्स के लिए खुशखबरी: अब दफ्तरों का चक्कर काटने की जरूरत नहीं, घर बैठे होंगे ये काम

कई बार EPFO मेंबर को अपने अकाउंट में जरूरत अपडेट करने होते हैं जैसे कि नाम जन्मतिथि या फिर वैवाहिक स्थिति बदलवाना। उन्हें इसके लिए EPFO के दफ्तर जाना पड़ता है और इसमें काम और समय का नुकसान भी होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वे अपने अकाउंट से जुड़ी जानकारियों को ऑनलाइन अपडेट करवा सकेंगे। यह जानकारी खुद EPFO ने दी है।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सदस्यों की संख्या और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की संख्या के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। फिलहाल इसके 7.5 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। ये सभी मेंबर हर महीने भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं।

हालांकि, कई बार EPFO मेंबर को अपने अकाउंट में जरूरत अपडेट करने होते हैं, जैसे कि नाम, जन्मतिथि या फिर वैवाहिक स्थिति बदलवाना। उन्हें इसके लिए EPFO के दफ्तर जाना पड़ता है और इसमें काम और समय का नुकसान भी होता है। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। वे अपने अकाउंट से जुड़ी जानकारियों को ऑनलाइन अपडेट करवा सकेंगे।

कैसे होगा अपडेशन का काम

EPFO ने शनिवार को कहा कि अब प्रोविडेंट फंड (PF) के सदस्य अपने डेटा में बदलाव या सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इससे संबंधित दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं।

ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर एक नया सॉफ्टवेयर शुरू किया है। यह मजबूत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) में सदस्य के डेटा को मान्य करता है। इसके जरिए पीएफ सदस्य अपने प्रोफाइल में नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता और आधार आदि को अपडेट या सही कर सकते हैं।

ब्याज दरों पर 7 जून को आएगा फैसला, क्या इस बार राहत देने के मूड में है आरबीआई?

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली MPC की बैठक 5 से 7 जून तक होगी। आरबीआई अपने फैसले का एलान 7 जून (शुक्रवार) करेगा। देश में पिछले साल फरवरी से बेंचमार्क ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह 6.5 फीसदी के उच्च स्तर पर बरकरार है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार भी आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा।

नई दिल्ली। इस बार रिजर्व बैंक (RBI) की आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होगी। लेकिन, इसमें रेट कट जैसी राहत मिलने की कोई खास उम्मीद नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि मुद्रास्फीति की चुनौती बनी हुई है, ऐसे में मौद्रिक नीति समिति (MPC) बेंचमार्क ब्याज दर में कटौती से परहेज करेगी।

देश में पिछले साल फरवरी से बेंचमार्क ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह 6.5 फीसदी के उच्च स्तर पर बरकरार है। हालांकि, आर्थिक विकास में तेजी के बीच रिजर्व बैंक दूसरी चीजों को अभी नजरअंदाज कर सकता है।

कब होगी MPC की मीटिंग?

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली MPC की बैठक 5 से 7 जून तक होगी। आरबीआई अपने फैसले का एलान 7 जून (शुक्रवार) करेगा। वहीं, लोकसभा चुनाव के नतीजे इससे तीन दिन पहले यानी 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

केंद्रीय बैंक ने पिछली बार फरवरी 2023 में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया था। तब से पिछली छह द्विमासिक नीतियों में दर को उसी स्तर पर बनाए रखा है। अगर 7 जून को फिर से ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होता। यह लगातार आठवां मौका होगा, जब RBI बेंचमार्क रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखेगा।

क्या है एक्सपर्ट की राय

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि पिछली MPC मीटिंग के बाद से आर्थिक हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। पीएमआई और जीएसटी कलेक्शन जैसे इंडिकेटर दिखाते हैं कि विकास सही दिशा में है।

उन्होंने आगे कहा मुद्रास्फीति पर चिंता बनी हुई है, भले ही पिछले आंकड़े 5 प्रतिशत से कम आए हों। भीषण गर्मी ने विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों को प्रभावित किया है। वहीं, मौसम विभाग ने सामान्य मानसून का अनुमान जताया है। इन सबसे यही लगता है कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा।

एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर का भी कहना है कि केंद्रीय बैंक से आगामी MPC बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि रिटेल इंफ्लेशन 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। उन्होंने कहा, 'हालांकि मुद्रास्फीति में कमी आ रही है, लेकिन लेकिन सितंबर में मानसून सत्र चीजें पूरी तरह साफ हो पाएंगी।'

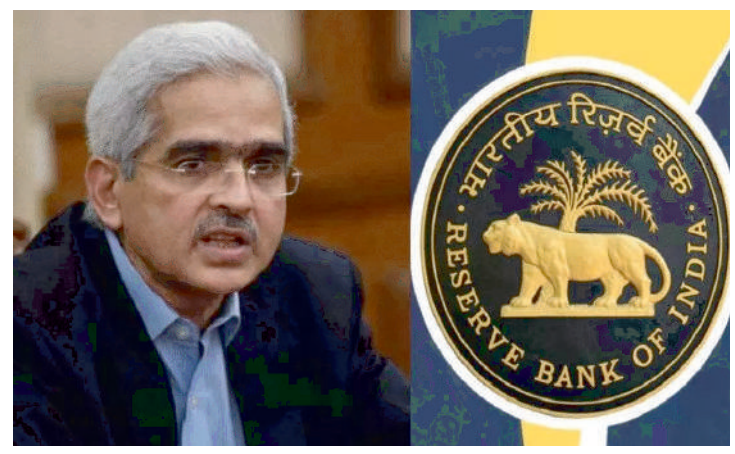

गौतम अदाणी फिर बने एशिया के 'धनकुबेर', मुकेश अंबानी को छोड़ा पीछे

गौतम अदाणी 111 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अब दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं अंबानी 109 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 12वें स्थान पर हैं। अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को 14% की तेजी आई। इससे गौतम अदाणी को बड़ा फायदा हुआ और वह दोबारा से एशिया के सबसे अमीर शख्सबन गए हैं।

नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी (Gautam Adani) की अदाणी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ समय से काफी तेज उछाल आया है और अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले वाले स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे निवेशकों के साथ गौतम अदाणी को भी काफी फायदा हुआ और वह दोबारा से एशिया के सबसे अमीर शख्स (Gautam Adani richest person in Asia) बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के मालिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है।

दुनिया के 11वें सबसे अमीर अदाणी

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स (Bloomberg Billionaires Index report) के अनुसार, गौतम अदाणी 111 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अब दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं, अंबानी 109 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 12वें स्थान पर हैं। अदाणी समूह की सभी कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार (31 मई) को 14 प्रतिशत तक की तेजी आई। अमेरिकी ब्रोकरेज जेफरीज का रुख अदाणी ग्रुप पर काफी बुलिश है, जिसने अगले दशक में 90 अरब डॉलर के पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है।

जेफरीज के रुख से निवेशकों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने अदाणी ग्रुप की कंपनियों में जमकर खरीदारी की। इससे अदाणी समूह की 10 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 84,064 करोड़ रुपये बढ़कर 17.51 लाख करोड़ रुपये हो गया। इससे पहली पीढ़ी के उद्यमी और अदाणी ग्रुप के मालिक गौतम अदाणी को मुकेश अंबानी से आगे निकलने में मदद मिली। अंबानी फिलाहल अपने सबसे छोटे बेटे अनंत की दूसरी प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए यूरोप में एक क्रूज पर हैं।

दूसरी बार अदाणी के सिर सजा ताज

यह दूसरी दफा है, जब 61 साल के गौतम अदाणी एशिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। इससे पहले यह ताज उनके सिर पर 2022 में में सजा था। लेकिन जनवरी 2023 में उनके 21 अरब डॉलर के विशाल साम्राज्य को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की नकारात्मक रिपोर्ट से झटका लगा। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि अदाणी ग्रुप ने अपना साम्राज्य धोखाधड़ी के माध्यम से बनाया है।

अदाणी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निवेशकों का भरोसा हिल गया और उन्होंने अदाणी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली शुरू कर दी। ग्रुप की कई लिस्टेड कंपनियों में लगातार लोअर सर्किट लगे। इसका असर गौतम अदाणी की दौलत पर भी पड़ा और उनके सिर से एशिया के सबसे रईस शख्स का ताज छिटक गया।

हिंडनबर्ग के झटके से कैसे उबरे अदाणी?

हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने जो नुकसान पहुंचाया था, उससे उबरने के लिए अदाणी ग्रुप ने ठोस रणीति बनाई। इसमें कर्ज को कम करना, फाउंडर के गिरवी रखे शेयरों को कम करना और अपने मुख्य व्यवसाय को मजबूत करना शामिल था। इस रणनीति ने बखूबी काम किया, क्योंकि अदाणी ग्रुप ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में रिकॉर्ड कमाई की है।

गौतम अदाणी 2022 में भी रिलायंस के मुकेश अंबानी को ही पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बने थे। जब उनकी दौलत घटी, तो मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। लेकिन, गौतम अदाणी एक बार फिर अमीरी के मामले में मुकेश अंबानी से आगे निकल गए हैं। वह इस साल की शुरुआत में भी कुछ समय के लिए एशिया के सबसे अमीर शख्स बने थे। लेकिन, इस बार उन्होंने अपनी पोजिशन को और पुख्ता किया है।

क्या करता है गौतम अदाणी का ग्रुप?

अदाणी ग्रुप भारत के कई हवाई अड्डों, देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह, मीडिया दिग्गज नई दिल्ली टेलीविजन, सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा फर्म, डेटा सेंटर और कई अन्य होल्डिंग्स का मालिक है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, 2024 में अब तक अदाणी की कुल संपत्ति 26.8 अरब डॉलर बढ़ी है। वहीं, अंबानी की संपत्ति में 12.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है।

पिछले हफ्ते गौतम अदाणी ने ग्रुप कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट में कहा था, ₹आगे की राह असाधारण संभावनाओं से भरी हुई है। अदाणी समूह आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अभी इसके सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं।'

पीएम किसान की 17वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार, 4 जून के बाद आएंगे पैसे?

4 जून यानी मंगलवार को आम चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इसी कड़ी में देश के किसान भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17 वीं किस्त 4 जून के बाद किसानों के खाते में आ सकती है।

नई दिल्ली। 4 जून यानी मंगलवार को आम चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इसी कड़ी में देश के किसान भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

कब आ रही है योजना की अगली किस्त?

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17 वीं किस्त 4 जून के बाद किसानों के खाते में आ सकती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जून के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद की जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि अभी तक सरकार की ओर से अगली किस्त जारी होने की तारीख को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है।

फरवरी में आई थी योजना की 16वीं किस्त

इससे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16 वीं किस्त फरवरी में जारी हुई थी। फरवरी में 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम योजना के तहत जारी की गई थी।

हर साल किसानों को मिलते हैं 6000 रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत देश के किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के पात्र किसानों को यह राशि 2000-2000 रुपये कर साल में कुल 3 बार दी जाती है।

यानी इस योजना के तहत पात्र किसानों के खाते में हर चार महीने में योजना की राशि जमा की जाती है। किसानों के अकाउंट में योजना की राशि ऑनलाइन ही ट्रांसफर की जाती है।

PM-KISAN: लाभार्थी लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

- आप भी पीएम किसान लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं-
- इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर आना होगा।
- अब यहां BENIFICIARY LIST पर क्लिक करना होगा।
- यहां राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक, गांव की जानकारी भरकर Get Report' टैब पर क्लिक करना होगा।

आंध्र प्रदेश से क्यों और कैसे अलग हो गया तेलंगाना? लंबी लड़ाई के बाद मिली नई पहचान, लेकिन कई मुद्दे अब भी अनसुलझे

तेलंगाना देश का 29वां राज्य है। आज (2 जून) ही के दिन लंबे आंदोलन के बाद 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का गठन किया गया था। आज यानी 2 जून 2024 को तेलंगाना 10 साल का हो गया है। लेकिन अपने अस्तित्व के लिए इस प्रदेश ने और यहां के लोगों ने करीब 49 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है।

परिवहन विशेष न्यूज

हैदराबाद। तेलंगाना देश का 29वां राज्य है। आज (2 जून) ही के दिन लंबे आंदोलन के बाद 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का गठन किया गया था। आज यानी 2 जून 2024 को तेलंगाना 10 साल का हो गया है। लेकिन अपने अस्तित्व के लिए इस प्रदेश ने और यहां के लोगों ने करीब 49 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है।

राष्ट्रपति ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को एक मार्च, 2014 को मंजूरी दी थी और दो जून, 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5(1) के मुताबिक, 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की साझा राजधानी होगी। इसी अधिनियम की धारा 5(2) में कहा गया है कि हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी होगी और आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी होगी।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं रहेगी

आज यानी 2 जून से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आधिकारिक संयुक्त राजधानी हैदराबाद नहीं रहेगी। हालांकि, आंध्र प्रदेश की अभी तक कोई स्थायी राजधानी नहीं है। अमरावती और विशाखापत्तनम को लेकर लड़ाई अभी भी अदालतों में चल रही है। बता दें कि आंध्र प्रदेश ने 2014 में विभाजन के तुरंत बाद हैदराबाद को राजधानी के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। एक राजनीतिक पर्यवेक्षक ने कहा कि दो तेलुगु राज्यों के बीच नवीनतम विभाजन प्रतीकात्मक होगा, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

वहीं, आंध्र के मौजूदा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि अगर वे सत्ता में बने रहते हैं तो विशाखापत्तनम को प्रशासनिक राजधानी बनाएंगे, और अमरावती विधानमंडल की सीट होगी और कुरनूल न्यायिक राजधानी होगी।

तेलंगाना के बारे में क्या आप ये जानते हैं?

- ये राज्य 1,12,077 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला है।
- तेलंगाना की जनसंख्या 3.50 करोड़ (2011 जनगणना के अनुसार) है।
- तेलंगाना राज्य उत्तर में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक, दक्षिण और पूर्व में आंध्र प्रदेश से घिरा है।
- तेलंगाना के कुछ बड़े शहरों के नाम हैं- हैदराबाद, वारंगल, निजामाबाद, नालगोंडा, खामम, करीमनगर।
- तेलंगाना का अपना गाना भी बनाया गया है। इसका शीर्षक है- 'जय जय हे तेलंगाना'

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच अनसुलझे हैं कई मुद्दे

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दोनों राज्यों के बीच आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की अनुसूची-9 और अनुसूची-10 में सूचीबद्ध विभिन्न संस्थानों और निगमों का विभाजन अब तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, लगभग 89 सरकारी कंपनियां और निगम नौवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।

इन कंपनियों और निगमों में आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम, आंध्र प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक विकास निगम और आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम जैसी राज्य-संचालित कंपनियां तथा निगम शामिल हैं। अधिनियम की 10वीं अनुसूची में आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी संघ, पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, आंध्र प्रदेश वन अकादमी, सुशासन केंद्र और आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी जैसे 107 प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र शामिल हैं।

हालांकि, सेवानिवृत्त नौकरशाह शीला भिड़े की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने अनुसूची-9 और अनुसूची-10 के संस्थानों के विभाजन पर सिफारिशें दी हैं, लेकिन मामला अभी अनसुलझा है। विभाजन के बाद बिजली आपूर्ति के बकाया भुगतान को लेकर भी दोनों राज्य विवाद में फंस गए हैं। जबकि कर्मचारियों का तबादला उन मुद्दों में से एक है जो अंतिम समाधान की प्रतीक्षा कर रहा है।

तेलंगाना अराजपत्रित अधिकारी संघ मध्य-हैदराबाद के अध्यक्ष एम. जगदीश्वर ने रविवार को 'पीटीआई' को बताया कि उन्होंने 18 मई को उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क को एक ज्ञापन सौंपा है और उनसे राज्य विभाजन के दौरान आंध्र प्रदेश को आवंटित हुए 144 तेलंगाना कर्मचारियों को वापस लाने के लिए सरकार से आग्रह किया गया।

ये कर्मचारी 2014 से आंध्र प्रदेश में काम कर रहे हैं। एक अन्य उदाहरण राज्य संचालित सड़क परिवहन निगम की संपत्ति को लेकर दोनों राज्यों के बीच असहमति है। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'पीटीआई' को बताया कि आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद में स्थित निगम की संपत्तियों में हिस्सेदारी मांगी है और टीएसआरटीसी ने इससे इनकार कर दिया है तथा इस पर असहमति जताई है।

टीएसआरटीसी को लगता है कि शीला भिड़े समिति द्वारा दी गई 'मुख्यालय' की परिभाषा के अनुसार ये संपत्तियां उसकी हैं। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को आंध्र प्रदेश में कर्मचारियों के लंबित तबादले और प्रत्यावर्तन को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का निर्देश दिया था। उन्होंने अधिकारियों से उन मुद्दों को हल करने के लिए कहा था, जहां दोनों राज्यों के बीच सुलह हो और अन्य लंबित मामलों पर तेलंगाना के हितों की रक्षा के लिए इस तरह से कार्य किया जाए।

तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लंबित मुद्दों तथा अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए 18 मई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो सकी क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर निर्वाचन आयोग से अपेक्षित मंजूरी 18 मई की रात तक नहीं मिली थी।

मुख्यमंत्री रेवन्थ रेड्डी ने अब निर्वाचन आयोग की मंजूरी मिलने के बाद ही मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के शासनकाल के दौरान फरवरी, 2014 में संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद दो जून, 2014 को जब तेलंगाना अस्तित्व में आया, तो यह एक दशकों पुरानी मांग की पूर्ति थी।

हैदराबाद को दो जून 2014 से 10 वर्षों की अवधि के लिए दोनों राज्यों की साझा राजधानी बनाया गया था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार हैदराबाद महानगर दो जून, 2024 से अकेले तेलंगाना की राजधानी होगा।

आंध्र प्रदेश सरकार का सचिवालय वर्ष 2016 में ही राज्य के अमरावती में स्थानांतरित हो गया था, जब तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे। नायडू ने अमरावती में एक विश्व स्तरीय राजधानी विकसित करने की योजना बनाई थी।

दिल्ली, यूपी-बिहार समेत भारत के अधिकांश हिस्सों में लू का कहर, आईएमडी ने मौसम को लेकर जारी किया अपडेट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को पूर्वानुमान लगाते हुए कहा कि 3 जून को देश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने की संभावना है। मौसम बुलेटिन में कहा गया है कि 3 जून को पंजाब हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली जम्मू संभाग हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है।

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को पूर्वानुमान लगाते हुए कहा कि 3 जून को देश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने की संभावना है। मौसम बुलेटिन में कहा गया है कि 3 जून को पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में चल रही लू की स्थिति और मानसून की शुरुआत की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को बताया गया कि आईएमडी के पूर्वानुमानों के अनुसार, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि इस साल देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सामान्य और सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया, "अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का अग्नि ऑडिट और विद्युत सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से किया जाना चाहिए।"

उन्होंने यह भी कहा कि जंगलों में अग्नि रेखाओं के रखरखाव और बायोमास के उत्पादक उपयोग के लिए नियमित अभ्यास की योजना बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को वन अग्नि की समय पर पहचान और उनके प्रबंधन में ₹वन अग्नि₹ पोर्टल की उपयोगिता के बारे में बताया गया।

देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के साथ, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने कई राज्यों में हीटस्ट्रोक से कम से कम 56 मौतों की पुष्टि की है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल के तट से टकराया और गुरुवार से पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा।

इस साल मानसून की शुरुआत दो दिन पहले हुई है, जबकि इसकी शुरुआत की सामान्य तारीख 1 जून है। इस साल, केरल में व्यापक प्री-मानसून बारिश हुई। 2023 में मानसून के मौसम (जून-सितंबर) के दौरान पूरे देश में बारिश, इसकी लंबी अवधि के औसत का 94 प्रतिशत थी।

आखिर क्यों नहीं मिल रहा इंडी गठबंधन को बहुमत? पूर्व कांग्रेस नेता ने बताया- मोदी तीसरी बार जीतेंगे लेकिन...

चुनावी नतीजे को लेकर पूर्व कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा 4 जून को जो परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला होगा। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। देश की जनता फिर एक बार नरेंद्र मोदी को देश के पीएम पद पर आसीन करेगी...4 जून के बाद विपक्ष के ये जितने नौसिखिये परिवारवादी पार्टियों के शहजादे हैं ये गुफाएं ढूंढते फिरेंगे...।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी और आगामी चुनावी नतीजों को लेकर भविष्यवाणी की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, ₹4 जून को जो परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला होगा। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। देश की जनता फिर एक बार नरेंद्र मोदी को देश के पीएम पद पर आसीन करेगी...4 जून के बाद विपक्ष के ये जितने नौसिखिये परिवारवादी पार्टियों के शहजादे हैं ये गुफाएं ढूंढते फिरेंगे...।"

अमीर लोगों को गरीबों की तुलना में डायबिटीज, डिप्रेशन और कैंसर का खतरा अधिक; सर्वे ने सबको चौंकाया

फिनलैंड के लगभग 2 लाख 80 हजार व्यक्तियों के जीनोमिक्स सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य डेटा पर आधारित उनके निष्कर्ष जर्मनी में चल रहे यूरोपीय सोसायटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के वार्षिक सम्मेलन में पेश किए गए। अध्ययन में सिफारिश की गई है कि पॉलीजेनिक जोखिम स्कोर को स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में जोड़ने से अनेक रोगों का पता लगाने में मदद मिल सकती है।

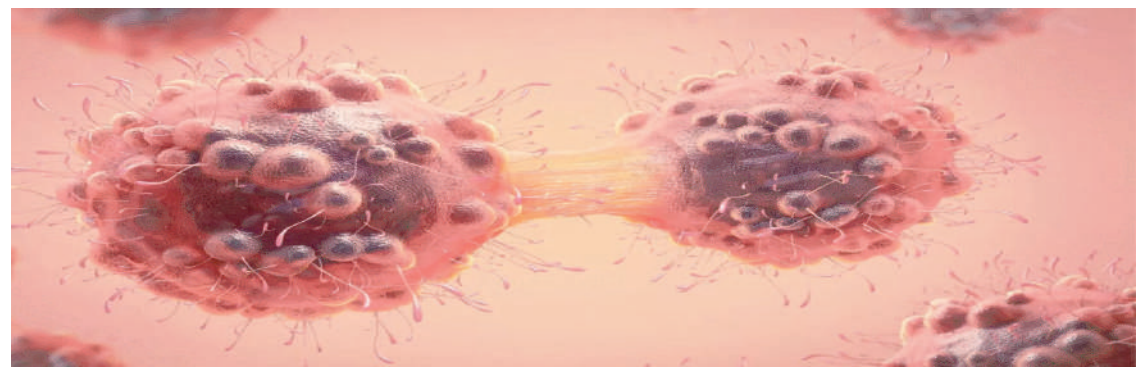

दिल्ली। एक अध्ययन में रविवार को खुलासा हुआ है कि डायबिटीज, डिप्रेशन और कैंसर का जोखिम आपकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर निर्भर कर सकता है। एजुकेशनल अचीवमेंट और व्यवसाय के आधार पर कमजोर (निम्न) सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले लोगों में डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसी जटिल बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होती है।

उनमें रूमेटोइड गठिया, फेफड़े के कैंसर, डिप्रेशन और शराब सेवन विकार जैसी कई अन्य जटिल बीमारियों के विकसित होने की आनुवंशिक (जेनेटिक) संवेदनशीलता (ससेप्टिबिलिटी) भी अधिक थी। फिनलैंड के हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के शोध के अनुसार, उच्च स्तर वाले लोगों में कुछ प्रकार के ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर विकसित होने का खतरा ज्यादा होता है। फिनलैंड के लगभग 2 लाख 80 हजार व्यक्तियों के जीनोमिक्स, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य डेटा पर आधारित उनके निष्कर्ष, जर्मनी में चल रहे यूरोपीय सोसायटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के वार्षिक सम्मेलन में पेश किए गए। अध्ययन में सिफारिश की गई है कि पॉलीजेनिक जोखिम स्कोर को स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में जोड़ने से अनेक रोगों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। यह समझना कि रोग जोखिम पर पॉलीजेनिक स्कोर का प्रभाव संदर्भ पर निर्भर है, आगे स्तरीकृत स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल की ओर ले जा सकता है।

यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन फिनलैंड (एफआईएमएम) में पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता फियोना हेगेनबीक ने कहा, ₹यह समझना कि डिजीज रिस्क पर पॉलीजेनिक स्कोर का प्रभाव संदर्भ पर निर्भर करता है और आगे स्ट्रेटिफाइड स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल को जन्म दे सकता है।

सावधान! बढ़ती गर्मी में लगातार कर रहे हैं AC का इस्तेमाल तो अस्थमा समेत ये बीमारियां होना तय!

तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग लू और गर्मी के जोखिम से बचने के लिए एसी का उपयोग कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर ने अब एसी को लेकर भी लोगों को आगाह किया है। डॉक्टर ने एसी के लंबे समय तक उपयोग से त्वचा और श्वसन संबंधी समस्याओं सहित कई स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ सकते हैं।

नई दिल्ली। भारत में इस वक्त सूरज आग उगल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में चिलचिलाती गर्मी का दौर चल रहा है। पंखा, कूलर और एसी के बिना एक घंटा काटना भी सोच से परे है। हीटवेव के कारण लोग घरों में राहत के लिए एसी चला कर रख रहे हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में एयर कंडीशनिंग (एसी) ही हैं जो लोगों को राहत पहुंचा रही है। वहीं, डॉक्टर ने अब एसी को लेकर भी लोगों को आगाह किया है।

डॉक्टर ने एसी के लंबे समय तक उपयोग से त्वचा और श्वसन संबंधी समस्याओं सहित कई स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ सकते हैं। डॉक्टरों ने बढ़ती गर्मी और एसी के बढ़ते उपयोग को देखते हुए रविवार को इसकी चेतावनी दी।

एसी के इस्तेमाल से कई स्वास्थ्य संबंधी खतरे

मणिपाल अस्पताल, बेंगलुरु के कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट सुहास एच एस ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, ₹लंबे समय तक एसी के संपर्क में रहने से कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं। इन खतरों में शामिल है- सूखी, परतदार और खिंची हुई त्वचा से लेकर सिरदर्द, सूखी खांसी, चक्कर आना और मतली, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, थकान और गंध के प्रति संवेदनशीलता शामिल है।₹

एसी में लंबे समय तक रहने से बचने की दी सलाह

डॉक्टर ने कहा कि एसी में ज्यादा रहने के कारण एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं और अगर एसी का उचित रखरखाव नहीं किया जाता है तो संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ठंड के संपर्क में लंबे समय तक रहने से बचने की सलाह दी है।

एसी में यह फिल्टर है बहुत जरूरी

सर गंगा राम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार एम वली ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि एयर कंडीशनिंग से जुड़ी चिकित्सा समस्या यह है कि उनमें उचित फिल्टरेशन नहीं होता है। इस फिल्टर को आदर्श HEPA फिल्टर कहते हैं जो अनुशंसित हैं या वे बहुत कम ब्रांडेड अच्छी कंपनी के एयर कंडीशनर में होते हैं। प्रदूषण के कारण यह फिल्टर बंद हो जाते हैं और संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है।

HVAC सेटअप में जोखिम अधिक

फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम के वरिष्ठ निदेशक और यूनिट हेड, इंटरनल मेडिसिन, सतीश कौल ने कहा कि घरेलू AC सेटअप की तुलना में वाणिज्यिक हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (HVAC) सेटअप में जोखिम अधिक है। हालांकि घरेलू AC कूलिंग सिस्टम और बैक्टीरियल संदूषण के बारे में बहुत अधिक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया कूलिंग कॉइल पर बायोफिल्म बनाते हैं और 90 प्रतिशत से अधिक समय तक AC के संपर्क में रहने वाले मनुष्यों में संक्रमण का कारण बन सकते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023